COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

Thirty-Third, Forty-third and Fiftieth Reports.

SHRI G.S. DHILLON (Taran Taran): I beg to present the following Reports of the Committee on Public Undertakings :—

(1) Thirty-third Report on action taken by Government on the recommendations contained in their Twenty-ninth Report (Third Lok Sabha) on Durgapur Steel Plant of Hindustan Steel Limited.

(2) Forty-third Report on Sindri Unit of Fertilizer Corporation of India Limited [Paras in Section II of Audit Report (Commercial), 1968].

(3) Fiftieth Report on action taken by Government on the recommendations contained in the Fifty-second Report of the Estimates Committee (Third Lok Sabha) on personnel policies of Public Undertakings.

12.24 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS*—*contd.*

MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING—*Contd.*

MR. SPEAKER : Now, today is the last day for the Demands. I hope, we will be able to finish one or two more demands before we guillotine all the demands in the evening at 6-30 P. M.

On the Steel and Heavy Engineering Ministry, the balance left is 2 hours. The Minister may reply at 3-0 Clock.

SHRI A. S. SAIGAL (Bilaspur) : May I suggest one thing ? We should forego the lunch hour today and give more time to the demands.

MR. SPEAKER : That will not solve any problem except that we lose our lunch. The Minister will reply at about 3-30 P.M.

श्री बेणी शंकर शर्मा (बांका) : अध्यक्ष महोदय, यहां रेलवे मंत्री मौजूद हैं। मैं उन का ध्यान जो कल बर्दवान के निकट रेलवे एक्सिडेंट हो गया है उसकी ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

MR. SPEAKER : You cannot get up like this. So many Ministers are there. Because so many Ministers are there, therefore, everybody can get up ? No please.

SHRI TULSIDAS JADHAV (Baramati) : Sir, what about that thing ....

Mr. SPEAKER : Order, order. I got a letter—I should not mention it or the person who gave me. There is no coordination between you.

MR. SPEAKER : Shri Kanwar Lal Gupta.

SHRI KANWAR LAL GUPTA (Delhi Sadar) : After lunch.

MR. SPEAKER : Shri Anbazhagan would like to speak now ? SHRI ANBAZHAGAN (Tiruchengode) Later.

MR. SPEAKER : All right. I will call somebody from the Congress side. Shrimati Ila Palchoudhuri—not here. Shri Saigal.

SHRI A. S. SAIGAL : If I am given a chance on the Finance Bill also, I will speak on this demand.

MR. SPEAKER : About the Finance Bill, I am not very sure what will happen there. How can I assure you ?

Shri Rabi Ray :

SHRI A. S. SAIGAL : I am prepared to speak. I want to speak on the Finance Bill also.

MR. SPEAKER : I called you; you were not ready. I have now called Shri Rabi Ray.

श्री रबि राय (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, यह मंत्रालय हमारे लिये बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है, जिस के ऊपर.....

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Today at 6.30 P.M. there will be this guillotine. After that, the Appropriation Bill will come. Will it be open to us to say something at that time regarding those Ministries in respect of which the Demands for Grants are guillotined. ?

MR. SPEAKER : The Appropriation Bill comes after all the Demands have been sanctioned. Therefore, you can say something when the Finance Bill comes and not at the time of Appropriation Bill.

*Moved with the recommendation of President.

SHRI S. M. BANERJEE : We will not be sanctioning; we will only be censuring. Here is the Order Paper where it is mentioned : Ministry of Steel and Heavy Engineering, Ministry of Law and Ministry of Health and Family Planning and Works, Housing and Urban Development. So, upto 6.30 P. M., the House is supposed to go upto the Ministry of Health and Family Planning. Naturally we cannot take up the other Ministries. So, we shall be passing the Appropriation Bill without voting the Demands of the other Ministries. Therefore, before we vote for or against the Appropriation Bill, we should be given an opportunity to speak on those Ministries whose Demands could not be discussed.

MR. SPEAKER : The Appropriation Bill comes after all the Demands have been voted. While guillotining, you will be voting all the outstanding Demands; the only thing is that you will not have made speeches there. The Appropriation Bill is not the appropriate time, but the Finance Bill is the appropriate time when you can mention the subjects which could not be discussed on the floor of the House. You must be given a chance; I agree with you, but that will be when the Finance Bill is taken up. Suppose, the Appropriation Bill is to be discussed; that will again take two days. It has to go to the Rajya Sabha tomorrow. Apart from this, the normal democratic practice has been to speak on them when the Finance Bill comes; Appropriation Bill is not the appropriate time for it. The Finance Bill is coming up tomorrow; certainly, you can speak at that time.

SHRI A. S. SAIGAL : My only request is this. We are going to guillotine the Demands of a number of Ministries. Will you, therefore, please see that we get more days to discuss the subjects pertaining to those Ministries? Please think over it......

MR. SPEAKER : I cannot answer this now. How can I answer off hand whether I can increase the time and all that ?

*श्री रवि राय : अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था कि यह मंत्रालय हम लोगों के लिये बहुत ही एक महत्व का मंत्रालय है, जिस के बारे में खुद रिपोर्ट में मंत्री महोदय ने बतलाया है कि :

"As on 31st March, 1968, the total investment of Government in Hindustan Steel amounted to Rs. 1072.5 crores...."

और उस के बाद कहा है कि :

"The cumulative loss incurred by the Company since its inception upto 31st March, 1968, amounted to Rs. 122.4 crores."

इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इस बार हम लोगों ने फौलाद के कारखाने पर 1 हजार, 72 करोड़ रु० जमा किया है। फिर उसी रिपोर्ट में मंत्री महोदय बतला रहे हैं कि 31 मार्च, 1968 तक हम ने 122 करोड़ रु० का घाटा उठाया है।

12.29 hrs.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आप खुद जानते हैं कि इस देश में जिस तरीके से हमारे सारे कारखाने चलते हैं उन के सम्बन्ध में नौकरशाहों और पूंजीपतियों के बीच में लगातार एक साजिश चल रही है कि पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग्स को बदनाम किया जाये। आज भी आप ने अखबारों में पढ़ा होगा कि फरीदाबाद में जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा है तब कांग्रेस अध्यक्ष की राय है कि चूंकि पब्लिक सेक्टर अन्डरटेकिंग्स घाटे में चल रही है इस लिये उन के ऊपर सरकार को ज्यादा पैसा नहीं खर्च करना चाहिये, उन के ऊपर प्राइवेट सेक्टर अर्थात् निजी क्षेत्र को पैसा खर्च करना चाहिये। दुनिया भर में निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र में आप देखेंगे कि निजी क्षेत्र में तो इंतजाम अच्छा होता है और उसमें बेईमानी होती है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र में खराबियां तो होती हैं लेकिन ईमान चलता है। लेकिन आज भारत में मैं देख रहा हूं कि निजी और लोक विभाग दोनों में बदइंतजामी और बेईमानी उच्च दर्जे पर चल रही है, इन दोनों का ही उसमें बोल बाला है और दोनों ने एक दूसरे की बुरी आदतों [को सीख लिया है। ऐसी अवस्था में लोक विभाग को साकार किये

[श्री रवि राय]

बिना, उसको ठीक रास्ते पर लाये बिना आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है।

अभी उस दिन पन्त जी ने इस बहस में इंटरवीन किया था । तब उन्होंने कहा था कि हम लोग पिक अप कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि हिन्दुस्तान एक प्राचीन देश है और इस प्राचीन देश में औद्योगीकरण को आगे बढ़ाने के लिये हम लोग कोशिश कर रहे हैं। हम पब्लिक सैक्टर को समाजवाद की आत्मा मानते हैं। समाजवाद को आगे बढ़ाने के लिये हम को सार्वजनिक क्षेत्र पर निर्भर करना पड़ेगा । सार्वजनिक क्षेत्र के जरिये ही समाजवाद इस देश में आना चाहिये । लेकिन हिन्दुस्तान में जिस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र का मामला चल रहा है इसमें हम को लगता है कि कुछ हद तक फिजूलखर्ची और शान शौकत को ही बढ़ावा मिल रहा है। नौकरवाहों को जिस तरह से सार्वजनिक क्षेत्र में प्रश्रय मिल रहा है, जिस तरह से प्रशासन पर खर्चा हो रहा है, उसको देख कर मैं दंग रह जाता हूं। हम को सार्वजनिक क्षेत्र को फिजूल-खर्ची और शान शौकत से मुक्त करना होगा और इसको अच्छे तरीके से चलाना होगा। इसके बिना पब्लिक सैक्टर का या पब्लिक अन्डरटेकिंग्ज का कुछ मतलब नहीं रह जायगा । हम तो यह मानते हैं कि वह सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है बल्कि असल में सरकारी क्षेत्र है, सरकार उनका सरकारीकरण ही करती है। चूंकि सरकारीकरण इन उद्योगों का हुआ है, इस वास्ते इन उद्योगों का जो महत्व है, जो मतलब है, वह सिद्ध नहीं हुआ है।

मैं आपको फिजूलखर्ची का एक नमूना बताना चाहता हूं । पिछले महीने की 29 और 30 तारीख को मैं और श्री जार्ज फरनें-डीज दोनों राउडकेला में थे। उस कारखाने का एक्सपेंशन हुआ है। श्री वी० वी० गिरि जो हमारे वाइस प्रेजीडेंट हैं वह वहां जाने वाले थे। उनके वहां पहुंचने के एक दिन पहले ही हम वहां पहुंच गये थे। वहां जिस प्रकार की ठाठवाट और ऐयाशी का हमने नमूना देखा उसको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । वहां उत्पादन नहीं हो रहा है। लेकिन एक्सपैंशन जो हो रहा है उसका उद्घाटन करने वह वहां जाने वाले थे। मुझ को और श्री जार्ज फरनेंडीज़ को मालूम नहीं था कि फौलाद के जो कारखाने हैं उनके तीन अपने हवाई जहाज़ हैं। उनके विशेष तौर पर हवाई जहाज़ चलते हैं। उन हवाई जहाज़ों में राउड़केला के जो मैनेजर साहब हैं श्री सिन्हा, वह चलते हैं। वह एक हवाई जहाज़ से उतरे। हमने पूछा कि ये हवाई जहाज़ किस के हैं ? क्या यह आ० ए० सी० की रेग्युलर फ्लाइट है ? हम लोग तो साधारण हवाई जहाज़ों में जाते हैं, कैरेवल में जाते हैं या आई० ए० सी० के जो हवाई जहाज़ हैं उन में आते हैं लेकिन वे इन में नहीं जाते हैं और उन्होंने तीन हवाई जहाज़ अपने ले रखे हैं तीन कारखानों के लिये और इन हवाई जहाज़ों में इन कारखानों के जो बड़े-बड़े अफसर हैं वे आते और जाते हैं। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि पब्लिक अंडर-टेकिंग्ज़ में किस तरह से खर्चीलापन और फिजूलखर्ची चल रही है। इस तरह की चीज़ों से हम लोगों को कुछ सबक लेना चाहिये।

सार्वजनिक क्षेत्र के तीन मापदण्ड होने चाहिये। सार्वजनिक क्षेत्र से पैसा ले कर हम देश में ज्यादा औद्योगीकरण करते हैं या नहीं करते हैं, पैसा जमा करते हैं या नहीं करते हैं, इनवैस्टमेंट करते हैं या नहीं करते हैं ? दूसरे, इन से हम को जो सामान मिलता है वह सस्ता मिलता है या नहीं मिलता है, उपभोक्ताओं को हम उसको सस्ता लसुभ करते हैं या नहीं करते हैं। तीसरे फौलाद के कारखानों में जो मजदूर काम करते हैं उनके लिये प्राइवेट सैक्टर की तुलना में हम कुछ अच्छा इंतज़ाम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं।

इन तीनों मापदण्डों से हम जब विचार करते हैं तो हम को पूरी असफलता ही हाथ लगती है। मैं आपको पब्लिक अंडरटेकिंग्ज़ कमेटी की रिपोर्ट जो कि 1967-68 की है, उसमें से कुछ पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। राउरकेला ने पहले आयरन ओर लेने के लिये एम० एम० टी० सी० से बातचीत की थी। एम० एम० टी० सी० भी एक सार्वजनिक क्षेत्र है। लेकिन उसके साथ कुछ अच्छा इन्तज़ाम नहीं हो पाया और इस वजह से कमेटी की रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछ निजी क्षेत्र के लोगों के साथ राउडकेला वालों का करारनामा हुआ जिस के बारे में कमेटी ने शिकायत की है। अपनी रिपोर्ट में इस कमेटी ने कहा है :

M/s. B. Patnaik (P) Ltd. orginally offered iron ore at Rs. 16.50 per tonne and Manganese ore at Rs. 26 per tonne. M/s. Misrilal Jain had originally offered iron ore at Rs. 17 per tonne and manganese ore at Rs. 27 per tonne. On the other hand M/s. K. C. Chapter & Sons had offered iron ore at Rs. 16.50 per tonne and had indicated that if an order for 1 lakh tonnes of iron ore was placed they would be able to bring down the price to Rs. 16 per tonne. Similarly M/s. Serajuddin & Co. had offered manganese ore at Rs. 25 per tonne although they could not make any definite commitment due to prior arrangement with MMTC. M/s. Baijnath Sarda had offered to supply iron ore at Rs. 17 per tonne.

The Committee is unable to understand why the Rourkela Steel Plant did not consider the offer for 1,00,000 tonnes of iron ore by M/s. K. C. Thaper at Rs. 16 per tonne. Similarly the matter could have been pursued further with other firms who had quoted low prices.

Instead of following this straight forward line of action the plant authorities preferred the procedure of negotiating with parties who had quoted higher prices for these raw materials. If negotiations with Ms. B. Patnaik Mines and M/s. Missila Jain could bring down the rates quoted by them for these ores there is every reasons to believe that similar negotiations with others would have brought down their rates. Thus the likelyhood of further lowering of prices was ruled out by negoatiating with certain chosen parties.

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अध्यक्षता में भी एक कमेटी बनी थी। कंट्रोलर की आर्गेनाइ-जेशन के बारे में आपने भी अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की थीं। आपने जो सिफा-रिशें की थी, उनके बारे में एक सरकार कमेटी बनी थी जिसका कहना है कि उनको अमल नहीं लाया जा रहा है और काम जिस तरह से होना चाहिये नहीं हो रहा है। एक सार्वजनिक क्षेत्र का दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने के साथ सहयोग नहीं हो रहा है। उस दिन पन्त साहब कह रहे थे कि हम लोग सहयोग करेंग, सार्वजनिक क्षेत्र के एक कारखाने का सार्वजनिक क्षेत्र के दूसरे कारखाने के साथ सहयोग होगा। मैं समझता हूं कि सरकार की यह नीति होनी चाहिये कि भिलाई, दुर्गापुर, और राउडकेला का जोकि सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने हैं, आपस में सहयोग होना चाहिये और इन को आपस में जहां तक हो सके, एक दूसरे से माल खरीदना चाहिये। साथ हो दूसरे सार्वजनिक क्षेत्र के जो कारखाने हैं, उन सब का और इनका आपस में सहयोग होना चाहिये और एक दूसरे से अपनी जरूरत की वस्तुएं इनको खरीदनी चाहियें।

सरकार कमेटी का जो कहना है, उसको भी मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। कुछ अफसर थे जो दोषी पाए गये। सरकार खुद लिखते हैं कि जब वह जांच करने गए तो उन्होंने जिन फाइलों की मांग की, जिन फाइलों की उनको जरूरत थी, वे उनको नहीं मिलीं। सरकार कमेटी का कहना है :

As a result of our investigation we have come to the conclusion that the state of affairs in the Steel Controller's office in the matter of office procedures leaves very much to be desired, as pointed out by the Khadilkar Committee in their Report also. We had, therefore, considerable difficulty in getting information on a large number of issues. Considerable time

[श्री रवि राय]

was also taken up in obtaining records and in getting the requisite information from the authorities concerned.

यह कहा गया था कि बोकारो के कारखाने में 1970 में उत्पादन शुरू हो जायगा। लेकिन अब सरकार ने एलान किया है कि एक साल बाद वह होगा। 1971 में उत्पादन शुरू होगा। मैं चाहता हूं सरकार सदन में स्पष्ट एलान करे कि कब बोकारो में उत्पादन शुरू होगा। मान लो फिर इस अवधि को बढ़ा दिया जाता है, 1971 के बाद कहा जाता है कि 1972 में उत्पादन शुरू होगा तब क्या होगा? अगर एक बार सदन में इस तरह का एलान कर दिया जाता है कि फलां साल में उत्पादन शुरू हो जायगा और उत्पादन तब शुरू नहीं होता है तो उस अवस्था में मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय का यह दायित्व हो जाना चाहिये कि अगर उत्पादन निर्धारित तिथि पर शुरू नहीं होता है तो वह इस्तीफा दे दें। कुछ न कुछ तो सार्वजनिक क्षेत्र का जो काम है वह ठीक ढंग से चलना चाहिये। कहीं न कहीं तो दण्ड का इस्तेमाल होना चाहिये।

नैशनल लेबर कमिशन ने एक स्टडी टीम बनाई थी इन पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्ज़ के बारे में। वह प्राइवेट अंडरटेकिंग्ज़ में जो लेबर काम करती है, उसके बारे में भी थी लेकिन उसकी रिपोर्ट के आधार पर मैं पब्लिक अंडरटेकिंग्ज़ के बारे में खास तौर पर कहना चाहूंगा। मैं मानता हूं कि रुपये पैसे के लिहाज़ से मजदूरों को आप इंसेंटिव नहीं दे सकते हैं। उनको इन्सेंटिव देने के लिये आपके पास पैसा नहीं है। लेकिन आप उनको मैनेजमैंट में हिस्सेदार तो बना ही सकते हैं। मैनेजमैंट में उनको हिस्सेदार बनाने के लिये उसने सिफारिश भी की थी। मैं श्री पुनाचा और श्री पन्त को बताना चाहता हूं कि इस स्टडी ग्रुप ने क्या कहा है:

The Study Group of the National Commission on Labour and labour problems in the public sector has rightly called for "motivation through association of workers" in the running of public undertakings. Such association should concern not merely questions like wages and welfare, but also matters which concern the management of the undertakings, namely, the financial position, production, sales, costs, higher productivity, etc.

लेबर कमीशन ने यह सिफ़ारिश की है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्ज़ में काम करने वाले मज़दूरों की मैनेजमैंट, प्रशासन, में हिस्सेदार बनाया जाये। इस सिफ़ारिश को स्वीकार करने और उसके अनुसार मज़दूरों के नुमायंदों को मैनेजमेंट में शामिल करने से उन लोगों को अधिक काम करने और अधिक उत्पादन करने की प्रेरणा मिलेगी और साथ ही पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग्ज़ में मैनेजमैंट और मजदूरों के बिगड़ते हुये रिश्तों में सुधार होगा।

आप जानते हैं कि बंगाल में एक सज्जन हैं श्री बिरेन मुकर्जी। उनकी एक इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी है। उसमें कई धांधलिया हुई हैं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय उन धांधलियों के बारे में जांच करायें हमारे दो प्रमुख वकीलों, श्री दफ़्तरी और श्री सीतलवाद, ने इस बारे में जो कुछ कहा है, मैं उसको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं:

Similarly, the entries in the Profit and Loss accounts are also not such as to place faithfully before the shareholders the true position in relation to shares. Both with regard to Balance Sheet and Profit and Loss Account, there clearly is failure to give a true and fair picture of the affairs....

उनकी सिफ़ारिश है कि कम्पनी ला बोर्ड के द्वारा या कमीशन आफ़ एनक्वायरी बिठा कर इस बारे में जांच होनी चाहिये। उन के अनुसार इस संस्था ने कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 77(2) में निहित बातों की अवहेलना की है और कहा है की जो करार किया गया है, वह अधिनियम की धारा 361 में निहित व्यवस्था की प्रवंचना करता है। कम्पनी ला बोर्ड में कुछ लोगों ने शिकायतें

की हैं, जिन का आधार श्री सीतलवाद द्वारा दिया गया उन का मत है। यहां यह बात महत्वपूर्ण है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जो निर्णय किया है तथा माननीय वकील ने जो अपने विचार प्रकट किये हैं, उन में विरोधाभास है। अतः यह एक वैधानिक मामला है। इस लिये कम्पनी ला बोर्ड को चाहिये कि वह कम्पनी से जवाब तलब करने के पश्चात विधि मंत्रालय और महाधिवक्ता से परामर्श करने के बाद इस सम्बन्ध में अपना निर्णय दे।

मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र, टाटा या बिरेन मुकर्जी के कारखाने, इस इन्तजार में रहते हैं कि कोई अवसर मिलने पर किसी प्रकार पब्लिक सैक्टर को बदनाम किया जाये। इस लिये मैं चाहता हूं कि श्री सीतलवाद और श्री दफ़तरी ने जो कुछ कहा है, उसके बारे में जांच होनी चाहिये और औद्योगिक विकास मंत्री, श्री फ़खरुद्दीन अहमद, की मदद से इस बारे में खुलासा करना चाहिये।

मैं इन अनुदानों का विरोध करता हूं।

श्री अ० सिं० सहगल (बिलासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सब से पहले मिनिस्ट्री आफ़ स्टील एंड हैवी इंजीनियरिंग की रिपोर्ट के पृष्ठ 30 की तरफ़ आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जहां एलाय स्टील प्लांट के बारे में कहा गया है : –

"The Report is currently being examined by HSL. After the examination is completed preparation of the Detailed Project Report for expansion of the Alloy Steel Plant will be taken up".

मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय अपने रिकार्ड को देख कर इस सदन को बतायें कि मेसर्ज दस्तूर कम्पनी की तरफ़ से यह रिपोर्ट कब पेश की गई और सरकार ने अब तक उ स के बारे में क्या फ़रदर स्टेप्स लिये हैं।

रिपोर्ट के पेज 31 पर सेंट्रल कोल वाशरीज आर्गेनाइज़ेशन आफ़ एच० एस० एल० के बारे में कुछ विवरण दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वाशरीज के सम्बन्ध में कोई नई योजना बनाई गई है या नहीं। कोयले की सब से बड़ी खदानें चिरमिरी से ले कर कोरबा तक फैली हुई हैं। उन वाशरीज के द्वारा थर्ड ग्रेड के कोयले में में तो कोई सुधार नहीं हो सकता है, लेकिन वाशरीज से निकलने वाला अन्य श्रेणियों का कोयला लोगों के लिये ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। इस लिये उस तरफ़ ध्यान देना बहुत जरूरी है।

रिपोर्ट के पेज 41 पर हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट और हैवी मशीन टूल प्लांट यूनिट इन एच० ई० सी० का उल्लेख किया गया है। यह बहुत जरूरी है कि उस को स्ट्रेंग्दन करने के लिये यथा सम्भव सब उपाय किये जायें, ताकि हमें इस समय जो लास हो रहा है, वह पूरा किया जा सके।

रिपोर्ट के पेज 14 पर इंडियन आयरन एंड स्टील कम्पनी के एक्सपोर्ट परफार्मेन्स का ब्यौरा दिया गया है। मंत्री महोदय ने अभी कुछ समय पहले इस काम को हाथ में लिया है, लेकिन अभी तक जो काम किया गया है, वह प्रशंसनीय है। मैं आशा करता हूं कि उन्होंने जिस तरह से रेलवेज में ख्याति प्राप्त की है, उसी तरह इस विभाग में भी करेंगे। 1967-68 में बिलेट्स, बार्ज, स्ट्रक्चर्ल्ज, शीट्स और पिग आयरन आदि चीजों का कुल 127,327.911 टन का एक्सपोर्ट किया गया था। आंकड़ों को देखने से मालूम होता है कि 1968-69 में इस बारे में स्थिति और अच्छी हो जायेगी। जैसा कि इस रिपोर्ट में बताया गया है, ये चीजें जापान, हांगकांग, फ़ारमोसा, थाईलैण्ड, फ़िलिपाइन्ज, आस्ट्रेलिया, मलेशिया और सिंगापुर आदि कई देशों को एक्सपोर्ट की जा रही हैं।

मैं चाहता हूं कि इन प्लांट्स में काम करने वाले इम्पलाइज को पार्टनरशिप में लिया जाये, उन को प्राफ़िट में कुछ हिस्सा दिया

[श्री रवि राय]

जायें और इस प्रकार उचित कार्यवाही कर के उन लोगों की यूनियन्ज़ का सहयोग प्राप्त किया जाये, ताकि हमारे उत्पादन में वृद्धि हो। जब इन प्लांटस में काम करने वाले एम्पलाईज़ वहां के मैनेजमैंट का पार्ट एंड पार्सल बन जायेंगे, तो वे हमारे काम में पूरी मदद देंगे।

दुर्गापुर स्टील प्लांट के बारे में बहुत सी बातें हम लोगों के सामने आई हैं। मैं उन के बारे में इस समय कुछ नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन यह स्पष्ट है कि भिलाई स्टील प्लांट और अन्य स्टील प्लांटस का कार्य हमारे देश के लिये बहुत महत्वपूर्ण है। वे हमारे देश के औद्योगीकरण में एक ऐतिहासिक भूमिका अदा कर रहे हैं और उन के द्वारा हमारा देश सैल्फ़-साफ़िशेंसी को प्राप्त करेगा। हमारे आपोज़ीशन के भाई यह एतराज़ कर सकते हैं कि यह रिपोर्ट ठीक नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो आंकड़े और तथ्य हमारे सामने रखे गये हैं, उन से मालूम होता है कि हमारे मित्रों का कहना ठीक नहीं है। हमारे मित्रों को इन सब आंकड़ों को देखना चाहिये और अनुभव करना चाहिये कि हम कितना काम कर रहे हैं।

स्टील एक बहुत जरूरी चीज देश के लिये और देश की उन्नति के लिये है। यदि हम चाहते हैं कि ऐग्रीकल्चर हमारा अच्छी तरह से मजबूत हो, हमारे किसान मजबूत हों तो उस के लिये लोहे की बहुत सख्त जरूरत हमें पड़ेगी। इस लिये हम आप से चाहते हैं कि जो ट्रैक्टर्स हम आज बाहर से खरीद रहे हैं उन ट्रैक्टर्स को अपने यहां बनावें और छोटे छोटे ट्रैक्टर्स बना कर के यदि काश्तकारों को हम दे सकें तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा काम हम करेंगे। इस के लिये हम आप की मिनिस्ट्री का और आप का ध्यान आकर्षित करेंगे। आप इस के ऊपर भी ध्यान दीजिए और छोटे छोटे ट्रैक्टर्स जितने भी बनवा सकते हैं, बनवाइए। जो बाहर से मंगाते हैं, वह जिस वक्त काश्तकार आता है खरीदने के लिये तो उस वक्त पैसे की वजह से वह चीज या तो उस के नाम पर नहीं मिलती या महीनों धक्के उसे खाने पड़ते हैं। इस लिये इस पर आप विचार कीजिए। आप के जो एम्पलाइज़ वहां पर काम कर रहे हैं, मैं उन को धन्यवाद देता हूं और आप के मंत्रालय को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने जो काम किया है उससे दरअसल हमारे देश को और हमारे देश की स्थिति को उन्होंने ऊंचा किया है। इन शब्दों के साथ मैं आप की डिमांड का समर्थन करता हूं।

SHRI ANBAZHAGAN (Tiruchengode): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I am really happy at the way in which the Minister of State replied on Friday to the criticisms levelled against the Ministry. Complaints that the Steel Ministry is not working in a fair way and that the administration is not efficient have been levelled since a long time. I hope that after the reply of the Minister of State, there is now a very good opportunity for them to rectify all the lacunae that are present and also to see that the impression that the public sector undertakings will not be efficient and will not be gainful is changed.

After having read the speech of the President of the Congress in the newspapers, the impression of the President of the Congress himself is to the effect that the utility of the public undertakings will be very poor and as such the country needs some sort of efficient changes and remedies so that the public utility services as well as the public undertakings are worked in a way that is useful in order to curtail the monopoly in the industrial sector.

One hon. Member the other day found fault with the public undertakings, and another hon. Member from the Congress bench was defending the public undertakings by saying that no one can expect any gain in public undertakings, thus giving the impression as if they are public utility services. I want the Ministry to note that public undertakings should not be treated as parallel to the public utility Services. Public utility services are established in order to give benefits to the ordinary people; they may incur some losses also.

But if they are public undertakings, only for the gestation period there may be some losses, but those losses should not continue, and if they continue, it will certainly create the impression that the object of the Government especially when they very often claim that they are socialistic in their mind is not fulfilled and the Government will certainly be criticised, and the people will not have any confidence in the Government administration in general. It will indirectly help the monopoly industrialists whose interest is certainly not the interest of the common man in this country.

Further, I would like to refer to one other point. In the fourth Five Year Plan, in the draft as laid on the Table of The House, they have felt that in the year 1972-73, there will be a gap certainly in the production of either iron ingots or finished steel. The gap is to be filled by new projects, new steel plants that are to come up. I shall read a portion here in order to justify my claim:

> "In view of the long gestation required in creating additional capacity for steel, action has to be initiated during the Plan for meeting the future requirements of steel and pig iron. Provision has been made for this purpose;"

I do not know for which particular project this provision has been made. Then, it says :

> "Demand for alloy and special steels is estimated at about 294,000 tonnes in 1973-74. The output from the Alloy Steel Plant at Durgapur supplemented by production from Mysore Iron and Steel Company and private sector projects is expected to meet these requirements, except for a few special categories."

The minister should certainly think about this.

There is a demand from the erst-while Madras State—now Tamil Nadu—from 1957-58 onwards to sanction the Salem steel plant. In the beginning, it was doubted whether Salem steel will be a fruitful one in view of the iron content of the ore being only 35 per cent. Actually, after investigation by some experts from West Germany and Norway and then by Dastur and Company and also by some Japanese experts it was found that because of the presence of other chemicals in that ore, it can be easily converted into ore with 60 per cent iron content and it will be economical. After getting these investigation reports, the State Government has requested the Centre to sanction the plant.

I shall now refer to the replies given by the Ministers in charge of the Steel Ministry from 1964 onwards. At one time, Mr. C. Subramaniam said, "Salem Steel plant will become a fact very soon." After the investigation made by the Japanese team, Mr. T. N. Singh replied as follows :

> "The Japanese team which studied the prospect of a steel plant in Salem has reported that a 250,000 tonne plant producing low alloy steels or a 500,000 tonne plant producing low alloy and mild steel would be viable and profitable. The location of the plant which would be based on Salem iron ore and Neiveli lignite has been suggested at a site about 14 KMs. from Salem."

This was his reply on 12th August, 1966 including the site. There have been so many requests, from the State Government. The ex-Chief Minister, Mr. Bhaktavatsalam, who was in charge before 1967, assured the State Assembly, when the opposition parties pressed the claim for Salem steel plant, that he had no doubt whatsoever in his mind about the Central Government coming forward and setting up the plant. He also said, if the Central Government is not able to find the necessary resources, the State Government will think on the lines of setting up the plan in its own sector with the permission of the centre. The responsibility fell on the shoulders of our late lamented leader, Mr. Annadurai, to request the Central Government and see that it is implemented within a short time.

13 hrs.

In his capacity as Chief Minister he has also given an assurance to the State Assembly that it will be implemented in the first year of the Fourth Plan. When the leaders of the Opposition there and some other hon. Members doubted the feasibility of such a statement getting materialised, Anna definitely said : "I have no doubt in my mind. I have not yet got a categorical reply from the Centre, but from the way in which Central Ministers including the

[SHRI ANBAZHAGAN]

Prime Minister and others are thinking about this, I think it is feasible and it will come up even in the first year of the Fourth Plan." But in the Draft of the Fourth Plan there is no reference whatsoever about the Salem steel plant. When they themselves find that there is a gap in the requirement as well as in the capacity of production in the year 1972-73, they should think of some other plant which will be able to produce some more steel, some more iron ingot and all that. For this I think the Salem steel plant is specially suited for a special type of alloy. It is not that other projects are not able to produce this, but when the other projects are not able to fill up the gap for a particular special type of alloy the suitability of Salem steel plant should be thought of twice before it is discarded on any account.

Furthermore, I would like to say that there is no tie between Hospet or the Vizag plant envisaged by the people responsible for that area or the Chief Ministers of those States. They can also have those plants. I may add that the Salem steel plant as originally envisaged was to produce only a quarter million tonnes in the beginning and only after that to reach the level of half million tonnes. For that the required amount of capital is only Rs. 100 crores. It may be Rs. 130 crores or Rs. 96 crores or Rs. 100 crores; it has to be finalised. The foreign exchange that may be involved is only about Rs. 36 crores to Rs. 40 crores. For this project the Japanese experts as well as some companies specialised in that sort of steel production have given an assurance to the State Government, when they met our Chief Minister, that it is possible, they will be willing to give the know-how and technical help and also the foreign exchange component. They also agreed to purchase the material produced at Salem. When they are willing to bear the foreign exchange component and also to take the material that is produced, I think there should be nothing that can be objectionable in setting up the plant at Salem.

Therefore, in view of the necessity in the Fourth Plan as well as in the Fifth Plan when there is bound to be a good demand for steel, especially in the context of our industrial sector having picked up after the one-time recession, we will be able to meet the future demand only if we have new steel plants. Furthermore, on behalf of Tamil Nadu I would like to say that it is not only the demand of DMK, the political party in power, it is also the demand of the Congress which was in power earlier. It is the demand of the entire people of Tamil Nadu.

SHRI NAMBIAR (Tiruchirappalli) : It is the demand of the entire people of Tamil Nadu.

SHRI ANBAZHAGAN : Including the Left Communists. When the people demand for such a project the Central Government should give much more consideration. I would like to comment also that out of more than Rs. 2,000 crores spent more or less on steel projects and connected industries most of it has been spent in the North-Eastern region. I do not grudge that. I am not saying that there should not be any development in the north-eastern region, Bihar, Madhya Pradesh or even Orissa or, for that matter, West Bengal. At the same time, I want the Ministry to think in terms of regional balance and removal of backwardness. If you want to have socialistic pattern of society, a vital industry such as steel, which is the backbone as described by the Minister of State, should be there throughout the country. That backbone should find a place in the bottom of this country, that is to say, the southern part of the country. In that you may include Andhra Pradesh and Mysore. I have no objection. Since we have got enough resources to start or establish the Salem steel plant, I would request the Minister and the Cabinet to take a final decision soon. Let the matter not hang in the air for a very long time. Already, much water had flowed down the bridge. I do not think the Planning Commission has given much thought to this aspect, because it is not even mentioned in the draft Plan. Even though Shri Venkataraman, Member, Planning Commission was the Industries Minister of Tamilnadu, I do not think he has cared to get this included in the Draft Plan. So, I would request the Minister to take up the question with the Cabinet and come to a final decision so that the people of Tamilnadu will get the steel plant, which is their legitimate demand for which they have been agitating for a long time.

13.07 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen hours of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at six minutes past Fourteen of the Clock.

[SHRI GADILINGANA GOWD *in the Chair*]

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING.—*Contd.*

श्री मधु लिमये (मुंगेर) : मेरी आपसे एक प्रार्थना है। दो दिन पहले, सम्भवतः शुक्रवार को, मैंने सिंथेटिक्स ऐंड केमिकल्ज़ के सम्बन्ध में सवाल उठाया था और यह कहा था कि आज चार बजे एक विशेष बैठक बम्बई में हो रही है, सिंथेटिक्स ऐंड केमिकल्ज़ का उसमें मसला आने वाला है कि क्या तुलसीदास किलाचन्द को सोल सेलिंग एजेंसी दी जाये। आप जानते हैं कि सोले सेलिंग एजेंसी कोलेकर, बिना कुछ परिश्रम किये पिछले साल उनको 22 लाख रुपया मिल गया और आगे आने वाले पांच सालों में वे डेढ़ करोड़ की मलाई खाने वाले हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि डी० जी० टी० डी० ने अपनी मार्फत इनको करीब करीब 30 प्रतिशत आर्डर दे रखे हैं। तो 30 प्रतिशत माल बेचने के लिये इनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है क्योंकि वह तो सरकार ही लेती है। तो उसके ऊपर वे क्यों कमीशन ले रहे हैं? मेरे इस प्रश्न पर परसों डिप्टी स्पीकर ने सरकार को यह आदेश दिया था कि मधु लिमये ने जो मामला उठाया है वह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लाइफ इन्स्योरेंस कारपोरेशन भी इसमें शेयर होल्डर है। आज लाइफ इन्स्योरेंस कारपोरेशन इसके बारे में क्या रुख लेने जा रहा है, उसके बारे में हम को चिन्ता है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या डिप्टी स्पीकर ने आपको कोई डायरेक्शन दिया है कि आप श्री फखरुद्दीन अली अहमद, कम्पनी ला मिनिस्टर से या वित्त मंत्री से बातचीत करके शार्ट नोटिस क्वैश्चन या कालिंग अटेंशन एडमिट करें और मंत्री यहां पर बयान दें।

MR. CHAIRMAN : The Deputy-Speaker will be coming in the Chair at about 3 O' Clock. You can raise it then.

श्री मधु लिमये : तो तब तक के लिये इनको क्या डायरेक्शन है ? मैं चाहता हूं कि मेरी बात श्री रघुरमैया के कानों तक पहुंचे। तीन बजे तक वे इसके बारे में कोई फैसला करें। इसके लिये आपको टेलेक्स से मेसेज भेजनी पड़ेगी क्योंकि चार बजे से सभा है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें लाखों रुपये का सवाल है। देश के पैसे के बारे में किसी को भी कोई चिन्ता नहीं है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि ट्रेजरी बैंचज में बैठने वाले लोग क्या कर रहे हैं। ··(**व्यवधान**)··

SHRI S. M. BANERJEE : Sir, before raising this issue, I had a talk with the Deputy Speaker also. We are raising this matter because a meeting is going to be held at 4'O Clock today and tomorrow also. There are two meetings. Now, by the time the Deputy-Speaker comes here, the mischief would have been done. We are not sure whether he will be coming here at 3 O'Clock. Even if he comes at 3 O' Clock, he may direct the Minister and then the Minister may not be present in the House. It may take time and the mischief will be done. When you are now occupying the Chair, whether you are Chairman or you are the Speaker and you direct the Minister to make a statement today.

SHRI S. KANDAPPAN (Mettur): Let the Minister make a statement.

MR. CHAIRMAN : I will have to go through the papers. I do not know what he has assured you. Until I go through the papers, I cannot decide anything. I cannot allow anything now.

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) चेयरमैन साहब, मैं एक बहुत ही सीरियस बात आपकी नोटिस में लाना चाहता हूं। जो कांग्रेसी मेम्बर पार्लमेंट के हैं उनको एक बड़ी शिकायत है, अखबार में यह बात निकली है कि जो हमारे डिप्टी ला मिनिस्टर, मु० यूनुस सलीम साहब हैं, उनके साथ ला-सेक्रेटरी ने मिस-बिहेव किया है।....(**व्यवधान**).... वह तो गिलोटीन हो।

[श्री रणधीर सिंह]

जायगी, हमें कोई मौका नहीं मिलेगा ।

MR. CHAIRMAN : Please resume your seat. The discussion of the demands pertaining to the Ministry of Law is being taken up today. You may express your views at that time.

श्री रणधीर सिंह : एक सेक्रेटरी की इतनी हिम्मत हो गयी मिनिस्टर के मुकाबले कि ला मिनिस्टर की हाजिरी में डिप्टी ला मिनिस्टर की इनसल्ट की गयी, और ऐब्यूसिव लैंगुएज इस्तेमाल की गयी । उस ला सेक्रेटरी के खिलाफ़ ऐक्शन लिया जाय, उस को सस्पेंड किया जाय ।

MR. CHAIRMAN : Please hear me. I have understood the point that you want to make. Immediately after the Demands in respect of the Ministry of Steel and Heavy Engineering are voted, the Demands pertaining to the Ministry of Law would be taken up and you can express your views at that time.

श्री रणधीर सिंह : मैं सारी पार्लियामेंट की तरफ़ से कह रहा हूं कि इतने भले डिप्टी ला मिनिस्टर के साथ एक मुलाजिम इस प्रकार का व्यवहार करे । इसमें हम सब की तोहीन है ।

SHRI A. S. SAIGAL : On a point of order.

श्री शशिभूषण (खारगोन) पार्लियामेंटरी अफेयर्स के मिनिस्टर बैठे हैं उन से आप कहिये कि यह सारे हाउस की तौहीन है ।

SHRI K. N. TIWARY (Bettiah) : The officers, howsoever great they may be, should not misbehave with Ministers..... (*Interruptions*)

SHRI RANDHIR SINGH : Drastic action should be taken against him.

MR. CHAIRMAN : I can understand the anxiety of the hon. members. They may express their views when they speak on the Demands of the Law Ministry.

MR. CHAIRMAN : That will not be guillotined. Immediately after the Steel Ministry's Demand are voted, those of Law will be taken up.

SHRI S. KANDAPPAN : The practice prevalent in this House is that, when serious concern is expressed on the floor of the House, it is for the Minister of Parliamentary Affairs to take note of it and convey the anxiety of the hon. members to the Minister concerned. Within the time that is available he can ask the Minister to make some statement. This is a matter about our economy and our administration. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN : I cannot give any ruling. I have already expressed my views.

SHRI A. S. SAIGAL : On a point of order.

MR. CHAIRMAN : Please resume your seat.

SHRI A. S. SAIGAL : I have to request you.....

MR. CHAIRMAN : No, no. Nothing will go on record.

SHRI A. S. SAIGAL :*

MR. CHAIRMAN : Mr. Tulshidas Jadhav.

श्री तुलशीदास जाधव (वारामती) : सभापति जी जो मांग इस वक्त सदन के सामने चल रही है उस के ऊपर मैं बोलना चाहता हूं देश में जितनी स्टील की गरज है वह गरज पूरी हो जाय इस लिये प्लानिंग हमने अख्तियार की है । तीन प्लान हो गये, चौथा प्लान अभी शुरू होने वाला है और स्टील और हैवी इंजीनियरिंग विभाग का झुकाव तेजी से पब्लिक सेक्टर की तरफ़ होना चाहिये, उस रीति से थोड़ा बहुत होता है । अपने देश में हम लोगों ने कोआपरेटिव और सोशलिस्टिक

*Not Recorded.

पैटर्न आफ़ सोसायटी की रचना कबूल की है और उस दृष्टि से देखा जाय तो जो बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं वे स्टेट के और सार्वजनिक हाथ में रहने चाहियें। लेकिन उस के साथ-साथ एक बात भी इस विभाग को ख्याल में रखनी चाहिये और वह यह कि प्राइवेट सेक्टर जो चलते हैं वे किस रीति से इकोनामिक होते हैं, और पब्लिक सैक्टर के क्यों नहीं इकोनामिक होते। इस तरफ ख्याल देने की जरूरत है। अभी तक अपोज़ीशन के लोग और उस में भी पी० एस० पी०, एस० एस पी० और कम्युनिस्ट भाई तात्विक दृष्टि से सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसायटी का मुआयना अगर करते हैं और हम भी करते हैं कि मीन्स आफ़ प्रोडक्शन जो हैं वे इंडिविजुअल प्रौपर्टी, औनरशिप के हाथ में न रहें और उसका प्रोडक्शन देश के लिये हो। उसमें प्रोफ़िटेबिलिटी जिस को कहते हैं, नफ़े की भावना न हो। इसका मतलब यह नहीं है कि उसका जो आउट पुट होगा, जो रिटर्न होगा उस में हमेशा नुकसान रहे, यह इसका अर्थ नहीं है। लेकिन उस के साथ साथ जो कर देने वाले लोगों का पैसा होता है तो चाहे सरकारी सैक्टर हो या कोआपरेटिव सैक्टर हो या कोई और सैक्टर हो, इंडिविजुअल सैक्टर के बजाय, उस के वह ट्रस्टी होते हैं। जिस प्रकार किसी ट्रस्टी के ताबे में कोई जायदाद होती है तो वह उसका इस्तेमाल अपने खुद के लिये नहीं करता, इसी तरीके से पब्लिक सैक्टर को चलाने की यही गरज है। हो सकता है कि वैयक्तिक नफाखोरी की प्रवृत्ति प्राइवेट सैक्टर में होने से उस में ज्यादा इन्सेन्टिव होता है। जब 1952 में मैं रूस में एक महीने तक था तो मैंने वहां जो बड़े बड़े उद्योग हैं उन को देखा, और खेती के बारे में या दूसरी और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को जो देखा तो पाया कि वहां स्टेट काम करती है। लेकिन वहां भी जब चर्चा की तो यह मालूम हुआ कि जैसा प्राइवेट इंडस्ट्री में एक इंसेंटिव होता है, उत्साह होता है ऐसा पब्लिक सैक्टर में नहीं होता। वहां भी यह नजर आया। लेकिन वह कोशिश करते थे। तो इसका मतलब यह नहीं है कि पब्लिक सैक्टर में कभी भी इन्सेंटिव नहीं आयेगी। हिन्दुस्तान के लिये यह बहुत जरूरी है और हमारे तत्वाज्ञान में यह लिखा है कि "वसुधैव कुटुम्बकम", अर्थात् हम एक फैमिली के आदमी हैं और जैसे फ़ैमिली में चार, पांच आदमी हों वह उद्योग करते हैं तो वह ज्यादा तेजी से और मेहनत से करते हैं यह समझ कर कि यह हमारा काम है। यही तत्वाज्ञान हमारे भारत में हर जगह है। तो इसका फायदा ले कर हम पब्लिक सैक्टर को ज्यादा से ज्यादा बढ़ायेंगे। लेकिन उस के साथ साथ हमें यह भी देखना चाहिये कि किसी को टीका करने के लिये मौका न मिले। उस टीका का मौका तब मिलता है जब हम देखते हैं कि जितना कैपिटल आउट ले है उस का उतना रिटर्न नहीं मिलता जितना कि वाजिव तौर से मिलना चाहिये। ऐक्यूरेट फ़िगर तो मैं नहीं दे सकता लेकिन दो परसेंट, एक परसेंट, आधा परसेंट पब्लिक सैक्टर के अंदर हमको मिलता है और प्राइवेट सैक्टर को देखा जाय तो उस में आठ, नौ और दस परसेंट तक रिटर्न होता है। जनता का पैसा जब हमारे हाथ में हैं और उसको सार्वजनिक उद्योगों में लगाने पर यह हाल होता है तो यह एक प्रकार से कर देने वालों को दगा देना है। जनता यह समझ कर कि हम ट्रस्टी हैं इसी लिये पैसा देती है, लेकिन अगर उस का इस्तेमाल इकोनामिकली न हो तो यह हमारी गलती है। और उस का अर्थ जनता यही निकालती है कि हम ठीक से काम नहीं करते। स्वतन्त्र पार्टी-वाले जो हैं जहां तक मैंने उन के भाषण सुने, यहां भी और बाहर भी, तो उन का यही हथियार है कि पब्लिक सैक्टर को खत्म किया जाय और प्राइवेट सैक्टर ज्यादा बढ़ाया जाय। उसमें इंटेंशन उन का खराब है ऐसा मेरा कहना नहीं है। उत्पादक का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़े, उस में कम्पटीशन हो, हैल्दी कम्पटीशन हो, बुरा कम्पटीशन मैं नहीं

[श्री तुलशीदास जाधव]

कहता, हैल्दी कम्पटीशन हो और माल में सुपीरियारिटी आ जाय । जो भी वस्तु वहां से तैयार होकर मार्केट में आय उसकी वाजिब कीमत मिल सके और बाजार में उसकी मांग हो यह उसका इंटेंशन है। जो भी उस के दुर्गण हों या पैसे का गलत इस्तेमाल होता है या और ऐक्सप्लाएटेशन होता है वह नहीं होना चाहिये यही उसका मेन औबजैक्ट है।

कल के कांग्रेस अध्यक्ष का फरीदाबाद में दिया गया भाषण जो मैंने सुना और पढ़ा उस में भी उन्होंने पब्लिक सैक्टर के बारे में एक शक का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि पब्लिक सैक्टर में जो आज इंडस्ट्रीज चलती हैं वह नुकसान में चलती हैं। जाहिर है कि हमें देश में उतने उत्पादन की आवश्यकता के अनुसार इस बारे में विचार करना चाहिये । कांग्रेस अध्यक्ष के उस भाषण से यह चीज साफ़ हो जाती है कि उन्हें भी पब्लिक सैक्टर जैसे कि आज चल रहा है उस के बारे में शक है। इसका मतलब यह निकलता है कि पब्लिक सैक्टर के बारे म हमें जिस रीति से देखने की गरज है उस रीति से अभी हम नहीं देख रहे हैं और इसी दोष की तरफ़ हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष ने इशारा किया है।

यह हो सकता है कि प्राईवेट सैक्टर में जितना पैसा डाला हुआ है उस पैसे का रिटर्न ठीक तरीके से न आता हो और प्राइवेट सैक्टर में जो कर्मचारी लगे हुये हैं उनके लिये आवास आदि अन्य आवश्यक सुविधाओं की माकूल व्यवस्था न हो पाई हो, वेलफेयर के काम जो कि उन के लिये होने चाहिएं वह न हो पाये हों जबकि दूसरी तरफ पब्लिक सैक्टर की इंडस्ट्रीज में प्लांट लगने के पहले ही कर्मचारियों और अफसरों के लिये क्वार्टर्स और बंगलों आदि का इंतजाम हो जाता है और इसी तरह और जरूरत से ज्यादा पैसा खर्च कर दिया जाता है और होता यह है कि जो कैपिटल सरकार द्वारा उस में लगाया जाता है उस का रिटर्न नहीं आता है। इस लिये यह जो पब्लिक सैक्टर में आज त्रुटि है उस की तरफ़ सरकार को गम्भीरतापूर्वक ध्यान देने की जरूरत है।

एक ओर दुनिया में इंग्लैण्ड अमरीका, फ्रांस, इटली आदि देश हैं जहां कि कैपिटेलिस्ट पैटर्न है और दूसरी ओर रूस व चीन आदि देश हैं जहां कि डिक्टेटरशिप औफ़ दी प्रोलोटैरियट है जोकि एक डिक्टेटरशिप वाला पैटर्न चलाते हैं। लेकिन हम ने अर्थात् भारत ने जो रास्ता अखत्यार किया हुआ है वह एक तीसरा रास्ता डैमोक्रेटिक सोशलिज़म का है। जाहिर है कि इस में हमारे ऊपर बहुत अधिक जिम्मेदारी आ जाती है। रूस और चीन आदि देशों में तो डिक्टेटरशिप तरीके से काम चलता है और कर्मचारियों को ८ घण्टे या १० घण्टे रोज़ काम करवाते हैं और अगर कोई दस घण्टे रोज़ काम न करे तो उसे सजा हो जायगी । इंग्लैण्ड और अमरीका में प्राइवेट इंटरपिनर्स में हैल्दी कम्पीटशन होता है।

SHRI DHIRESWAR KALITA (Gauhati) : This is false.

श्री तुलशीदास जाधव : मेरे विचार में जो बात थी उसे मैं ने हाउस के सामने रख दिया है। अब अगर उन माननीय सदस्य के विचार में वह ग़लत हो तो वह अपने भाषण में उसे दुरुस्त करें या बाहर बैठ कर इस बारे में चर्चा करें। यह हो सकता है कि उस पार्टी में रहने के कारण मेरे से ज्यादा जानकारी रखते हों लेकिन मैंने जैसा इसे समझा है उसे रखा है। जहां तक मैंने समझा है या पढ़ा है अथवा रशियन लोगों से चर्चा की है उसके आधार पर मैंने अपना वह मत व्यक्त किया है, हो सकता है कि उनका विचार इस से भिन्न हो और मैं उन से इस बारे में झगड़ा नहीं करना चाहता । मेरा किसी से भी कोई झगड़ा नहीं है, न रूस से न अमरीका व इंग्लैण्ड से और मेरे वह जो भाई उधर बैठे हैं उन से भी कोई झगड़ा नहीं है। दरअसल

मैं तो यह चाहता हूं कि आज पब्लिक सैक्टर में जो ख़ामियां हैं, उस के कामयाब होने में जो दिक्कतें व बाधाएं हैं वह दूर हों। मेरे यह सुनने में आया है और देखने में भी कहीं कहीं पर आया है कि पब्लिक सैक्टर की इंडस्ट्रीज में पैसे की फिजूलखर्ची होती है, जितना स्टाफ़ काम के हिसाब से होना चाहिये उस से ज्यादा लोग रख लिये जाते हैं तो यह ठीक व उचित बात नहीं है और इसका निदान होना चाहिये। जहां काम के लिहाज़ से 2 आदमी आवश्यक हों वहां अगर 10–12 रख लिये जायेंगे तो जाहिर है कि वह धंधा घाटे में चलेगा। इसलिये जरूरत इस बात की है कि चाहे भिलाई हो, दुर्गापुर हो अथवा बोकारो का स्टील प्लांट हो वहां उतने ही आदमी रखे जायें जितने कि काम के लिहाज़ से रखने आवश्यक हों। अगर उन पब्लिक सैक्टर इंडस्ट्रीज़ के ऊपर आप आ० सी० एस० अफसरान बतौर ऐडमिनिस्ट्रेटर रखते हैं जोकि ला ऐंड आर्डर मेटन करने का काम करते रहते हैं और इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी नहीं रखते ऐसे लोगों को रखने से कोई लाभ नहीं होगा। मैं चाहूंगा कि इन पब्लिक सैक्टर इंडस्ट्रीज के लिये आप अनुभवी और कुशल व्यक्ति लीजिये और इसके लिये आवश्यक हो तो प्राइवेट सैक्टर से कुशल और अनुभवी लोग कुछ ज्यादा पैसा खर्च करके भी ले लीजिये ताकि हमारी पब्लिक सैक्टर की इंडस्ट्रीज कायदे से चल सकें और मुनाफ़ा कर के दिखला सकें। ऐसा होने से देशकी औद्योगिक उन्नति सम्भव हो सकेगी।

उदाहरण के लिये मैं आपको बतलाऊं कि नरसिंघगिरिजी स्पिनिंग ऐंड वीविंग मिल्स जोकि बन्द हो गयी थी उसे सरकार ने अपने कब्जे में ले कर बम्बई के एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट मारू को उस मिल को चलाने के लिये दे दिया। उन्होंने उसे अच्छी तरह से चला कर दिखाया। मेरा कहना है कि पब्लिक सैक्टर को कामयाब करने के लिये हम ऐसे अनुभवी व कुशल प्राइवेट सैक्टर में काम करने वालों की सहायता व सहयोग प्राप्त करें। इसके अलावा पब्लिक सैक्टर में जो पैसे का अपव्यय होता है वह भी सरकार को बन्द करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त देश में काफ़ी इंजीनियर्स आज बेकार बैठे हुये हैं। सरकार को चाहिये कि उनका ज्यादा से ज्यादा कारगर ढंग से इस्तेमाल किया जाय। हालत यह है कि हमारे देश में तो काफी तादाद में इंजीनियर्स बेकार बैठे हुये हैं जबकि महाराष्ट्र के एक सज्जन के बारे में मुझे जानकारी है कि वह अमरीका में 4 वर्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा लेकर हिन्दुस्तान आने को हुए तो वहां अमरीका में उन्हें कहा गया कि 10–15 लाख रुपये की सहायता उन्हें मिल सकती है और वह अपना इंजीनियरिंग का धंधा यहां शुरू कर सकते हैं लेकिन उस महाराष्ट्र के युवक ने उत्तर दिया कि वह हिन्दुस्तान में जाकर काम शुरू करेगा। जब वह यहां हिन्दुस्तान में आया तो तीन, चार वर्ष उसे आवश्यक लाइसेंस आदि मिलने में लग गया। जब मेरे साथ उसकी मुलाकात हुई, जब वह मेरे पास आया तो उस ने कहा कि अमरीका में मेरे लिये काम शुरू करने की इतनी सहूलियत थी लेकिन यहां हिन्दुस्तान में उसे शुरू करने में इतनी दिक्कतें पैदा होती हैं, इसलिये मेरा कहना है कि यह जो दफ्तरी दिक्कतें आज लोगों को होती हैं, लाइसेंस और परमिट आदि मिलने की वह दिक्कतें दूर की जायें ताकि लोग धंधों में लग सकें।

आइडिल कैपेसिटी को हमें जैसे भी हो हटाना है। इतना ही एक्सपैंशन करें जितना कि आवश्यक हो। बहुत सारी मशीनें लगाना जोकि इस्तेमाल न आयें गलत चीज़ है। हमें देखना चाहिये कि हमारी मशीनें बगैर काम के ऐसे ही आइडिल न पड़ी रहें।

दूसरी बात यह है कि सरकार वहीं पर प्लांट लगाये जहां कि उस की आवश्यकता हो और स्टील पंटल लगाने

[श्री तुलसीदास जाधव]

के लिये जो प्रैशर उस पर डाला जाता है कि एक स्थान से स्टील प्लांट हटा कर अमुक स्थान पर ले जाया जाये तो सरकार को इस बारे में दृढ़ता का परिचय देना चाहिये। अब जैसे एक स्टील प्लांट अपने वहां अर्थात् विजिगापट्टम में बैठाने के बारे में श्री अमृत राव खुद को आग लगा लेने की धमकी दे रहे हैं तो इस या ऐसे और जो एजिटेशन होते हैं कि एक स्टील प्लांट यहां से हटा कर वहां पर ले जाया जाये तो सरकार को इस बारे में किसी तरह की कमजोरी नहीं दिखानी चाहिये। प्लांट जहां मुनासिब हो वहीं वह लगायें। सरकार को पब्लिक सैक्टर की इंडस्ट्रीज के बारे में विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये क्योंकि इस में लोगों का अर्थात् आम जनता का पैसा लगा हुआ है, स्टील और हैवी इंजीनियरिंग में काफी पैसा लगा हुआ है और इस को ऐसे सुचारु ढंग से चलाने की सरकार व्यवस्था करे ताकि अभी जो लोगों के मन में एक शंका है और खुद कांग्रेस अध्यक्ष तक ने इस बारे में शंका प्रकट की, उन्हें शंका करने की जरूरत न पड़े और यह देश का उत्पादन बढ़ायें और साथ ही इन में मुनाफ़ा भी हो। अभी जो एक पब्लिक सैक्टर के बारे में कुछ लोगों को आशंका है जैसे कि कांग्रेस अध्यक्ष ने प्रकट की और उन्होंने कहा कि चूंकि यह घाटे में चलते हैं इसलिये प्राइवेट सैक्टर में घाटे वाले उद्योगों को दे दिया जाये और दूसरी तरफ़ हमारी प्राइम मिनिस्टर हैं जोकि उसी स्टेज पर कहती ह कि हमें अपने पब्लिक सैक्टर को बढ़ाना चाहिये, यह जो विचारों का कंट्राडिक्शन है वह हट जाये और पब्लिक सैक्टर के काम में लगे हुए लोगों के अन्दर हम यह भावना लायें कि वह इस काम को वैसी ही लगन व ईमानदारी के साथ करें जैसे कि वह अपने घर का काम करते हैं। जब तक यह भावना हम अपने अफसरों और कर्मचारियों में जोकि पब्लिक सैक्टर में लगे हुये हैं नहीं ले आ पायेंगे तब तक हम अपने उद्देश्य में कामयाब नहीं हो पायेंगे। बस इतना ही मुझे कहना है।

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : सभापति महोदय, जो रिपोर्ट मंत्री महोदय ने सदन के सदस्यों के सामने रखी है उस से क्या स्थिति है उस विभाग की इस का ज्ञान नहीं होता है। जो कैपेसिटी आइडिल पड़ी हुई है, मैनेजमेंट के बारे में, रैड टैपिज्म के बारे में, प्रोडक्शन के बारे में जो डाईवर्सिफिकेशन किया है उस के बारे में उस का क्या असर पड़ा यह इस रिपोर्ट में नहीं बतलाया गया है। इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति हमारा यह मंत्रालय किस स्थिति में है इस का ज्ञान उसे बिलकुल नहीं होता है।

सभापति महोदय, यह मंत्रालय और उसकी पब्लिक सैक्टर इंडस्ट्रीज कैसे चल रही हैं इस के बारे में मुझे कहने की जरूरत नहीं है। स्वयं कांग्रेस अध्यक्ष श्री निजलिंगप्पा ने एक सर्टिफिकेट दे दिया है। उस सर्टिफिकेट के बाद इस सरकार की आंखें खुल जानी चाहियें। मैं और मेरी पार्टी पब्लिक सैक्टर के खिलाफ नहीं हैं। हमारे लिये पिब्लिक सैक्टर टैबू नहीं है। हम चाहते हैं कि पब्लिक सैक्टर बढ़े। हम चाहते हैं कि पब्लिक सैक्टर और प्राइवेट सैक्टर बराबर बराबर चलते रहें और दोनों में फ्री कम्पिटीशन हो। लेकिन जिस तरह से पिछले बाइस सालों से पब्लिक सैक्टर चल रहा है, उस को देखते हुई उन सब लोगों को जो पब्लिक सैक्टर में विश्वास करते हैं और अपने को समाजवादी कहते हैं, यहां तक कि कांग्रेस के अध्यक्ष को भी, यह कहना पड़ रहा है कि आज रिथिंकिंग की जरूरत है और हमारा पब्लिक सैक्टर ठीक काम नहीं कर रहा है। आज फिर उन्होंने कांग्रेस सैशन में कहा कि अगर इस बात से सरकार यह समझती है कि मैं ने उस पर कोई चोट की है, तो मैं बतलाना चाहता हूं कि मैंने चोट की है और चोट करने के लिये ही मैं ने यह कहा है। यह मैं ने अभी रेडियो में सुना है।

हमारे कांग्रेस के प्रेजिडेंट के जो विचार हैं उनकी हमारे दोस्तों ने, जिन में श्री रवी राय

भी हैं, नुक्ता चीनी की है। लेकिन मैं उनके साथ पूरी तरह सहमत हूं। आज सरकार ने पब्लिक सैक्टर में साढ़े तीन हजार करोड़ रुपया लगा रक्खा है। वह लोगों का रुपया है। वह किसी मंत्री या अफसर का रुपया नहीं है। इस लिये सरकार को कोई हक नहीं है कि वह इस रुपये को नाली में बहाये ; 1100 करोड़ रु० स्टील प्लान्ट्स में लगा हुआ है और उसमें करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है। अगर आप इस मंत्रालय के इतिहास को देखें तो इस में कई कमिशनों और एन्क्वायरी कमेटियों की रिपोर्ट आई हैं, दर्जनों कमेटियां बनी हैं, लेकिन यह हाथी वैसे का वैसा ही चल रहा है। इस में कोई अन्तर नहीं आया ! मैं कह सकता हूं कि आज जो पब्लिक सैक्टर है यह माडल है माल-ऐडमिनिस्ट्रेशन का, करप्शन का, फैवरिटिज्म का, टाप-हैवी ऐडमिनिस्ट्रेशन का। दुनिया में जिस देश ने भी पब्लिक सैक्टर प्रोजेक्ट्स बनाये हैं, उन में से कहीं भी हमारे देश जैसी इनएफिशिएन्सी नजर नहीं आती।

हमारे मंत्री महोदय बड़े अच्छे आदमी हैं, शरीफ आदमी हैं। मैं उन से कहना चाहता हूं कि

Minor adjustments won't do. We require a major operation in this Ministry. Unless you are able to do it, you will be a complete, miserable, failure.

इस लिये मेरा कहना यह है कि अगर आप इस में कुछ करना चाहते हैं तो आप को इस में एक काम्पिटेंट डाक्टर की तरह से मेजर आपरेशन करने की जरूरत है। आज जिस तरह से हमारे देश में पब्लिक सैक्टर मिस-बिहेव कर रहा है, उस से लोगों के दिमाग में यह सन्देह हो रहा है कि कहीं यह आइडियोलॉजी तो गलत नहीं है। अगर आप अपनी इस आइडियोलोजी को देश के सामने प्रूव करना चाहते हैं तो आप को इस पब्लिक सैक्टर को चला कर दिखाना होगा। जिस पब्लिक सैक्टर में १२ परसेंट का नफा होना चाहिये उसमें आज आप लास दिखा रहे हैं। अगर प्राइवेट सैक्टर ठीक काम नहीं करता, ज्यादा पैसा चार्ज करता है और प्रोडक्शन कम करता है तो आप कानून बना कर उस की सुविधायें बन्द कर देते हैं, लेकिन चूंकि आप प्रिविलेज्ड क्लास हैं, आप के पास ताकत है, कानून है, जो लोग मिसबिहेव करते हैं उन को आप ठीक कर सकते हैं, लेकिन चूंकि जनता आप को देख नहीं सकती है, इस लिये आप कुछ करते नहीं है। मेरी मांग है कि आप को ज्यादा समय नहीं बिताना चाहिये, आप को एक आदर्श रखना चाहिये किस किस तरह से पब्लिक सैक्टर चलाया जाता है।

लोगों का रुपया ड्रेन में न जाय, हमारे यहां का रुपया बरबाद न हो, आज रुपया बाहर से भी आ रहा है, टैक्स-पेअर का भी रुपया है। सब का ठीक से इस्तेमाल हो आप को इस का ध्यान रखना चाहिये। आज चूंकि रुपया बाहर से आ रहा है, जिस के दबाव में आ कर सरकार ने बड़ा भारी कदम डिवेलुएशन का उठाया है, उन के दबाव में आ कर, क्योंकि हम को बाहर से सामान लेना पड़ता है, हम ने ऐग्रीमेंट्स किये। चूंकि हम को बाहर से शस्त्र लेने पड़ते हैं, इस लिये हम ने देश के हिस्से को कुर्बान कर दिया पैसा उधार लेने के लिये। आज आप नालियों में हमारा पैसा बहा रहे हैं, इस को देश बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस लिये इस का इलाज होना चाहिये। मेरी मांग यह है कि आज जो हमारा पब्लिक सैक्टर है उस को जब तक वह कंसोलिडेट न कर ले, उस को अच्छी तरह से न चलाये, तब तक उस को इसे और ज्यादा एक्स्पैन्ड नहीं करना चाहिये। यही बात श्री निजलिंगप्पा ने कही है और मैं उन से सहमत हूं।

डा० महादेव प्रसाद (महाराजगंज) : आप हमारे साथ आ जाइये।

श्री कंवरलाल गुप्त : आप कहां इस्तीफा दे रहे हैं ? आप के प्रेजिडेंट हमारे साथ आने वाले हैं। विचारों से तो वह आ भी गये। आज

[श्री कंवर लाल गुप्त]

यूनाइटेड फ्रंट की तरफ प्रधान मन्त्री जा रही हैं। प्रेजिडेंट दूसरी तरफ चले गये। आज यह गवर्नमेंट एक थ्री लेगेड रेस की तरह से है। उस में भी तीन टांगें होती हैं बजाय चार के, लेकिन कांग्रेस तो दो ही टांग की पार्टी है और एक उत्तर की तरफ जाती है और दूसरी दक्षिण की तरफ जाती है। प्राइम मिनिस्टर कहती हैं कि पब्लिक सैक्टर के लिये ज्यादा रुपया चाहिये और प्रेजिडेंट दूसरी बात कहते हैं। नतीजा वह होता है जो आज हो रहा है। इस लिये मेरा कहना यह है कि पहले कंसोलिडेट किया जाये। पहले इस को आप ठीक रास्ते पर चलाइये, इस में जिस आपरेशन की जरूरत हो वह आपरेशन कीजिये, उस के बाद इस को एक्स्पैन्ड कीजिये। हमें इस में कोई एतराज नहीं होगा। बल्कि खुशी होगी क्योंकि हम यह भी नहीं कर सकते कि एक सरमायेदारी सिस्टम में गवर्नमेंट को छोड़ दें। मैं जानता हूं कि सरमायेदार भी एक्स्प्लायट करते हैं। इस लिये दोनों का आपस में कम्पिटीशन हो, मैं यह चाहता हूं।

मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जो आप का टार्गेट था कि इतने समय तक यह स्टील प्लान्ट कम्प्लीट होना चाहिये या इतना रुपया इस में लगेगा, जितने भी स्टील प्लान्ट आप के बने हैं उन में से क्या एक भी प्रोजेक्ट समय की अवधि में बन पाया है या जितना रुपया लगना था उस में वह खत्म हो गया है? आप को आश्चर्य होगा कि जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन में से एक भी ऐसी नहीं जो निर्धारित समय की अवधि के अन्दर पूरी हुई हो। कोई एक साल आगे चली गई, कोई दो साल और कोई तीन साल। साथ ही जितना भी रुपया प्रोवाइड किया गया था, हर एक उससे आगे चली गई। बोकारो के अन्दर भी यही हो रहा है। आप उस को साल ब साल बढ़ाते चले जा रहे हैं और मुझे को पूरा विश्वास है कि जो आप का टार्गेट था उस वक्त तक आप उस को पूरा नहीं कर पायेंगे। बोकारो के अन्दर 50 लाख रु० से ज्यादा का नुकसान हो रहा है। इस लिये आप को अपने टार्गेट बढ़ाने नहीं चाहिये। जिस तरह आप बोकारो को चला रहे हैं, उस के लिये आप के पास टार्गेट होना चाहिये। हर एक क्वार्टर पर रिपोर्ट आनी चाहिये। प्राग्रेस रिपोर्ट आनी चाहिये कि जो टार्गेट आप ने रखे हैं वह पूरे हुये या नहीं और जहां पूरे नहीं हुये वहां उन को क्यों नहीं पूरा किया गया। बहाने तो आप अक्सर दे देते हैं। आप टार्गेट दीजिये। अगर आप देखें कि फलां अफसर ने उस टार्गेट को पूरा नहीं किया है, तो उस अफसर को हटा दिया जाये। इस का और कोई दूसरा रास्ता नहीं है जब तक आप पर्सनल रिस्पांसिबिलिटी फिक्स नहीं करेंगे। प्रोडक्शन के बारे में, टार्गेट के बारे में कि यह प्रोडक्शन होना चाहिये और यह यह टार्गेट होना चाहिये निश्चय होना चाहिये और जो अफसर उस को पूरा नहीं करता उस को वहां रहने का अधिकार नहीं है। साथ ही जो टार्गेट से ज्यादा काम करे उस को इनाम भी दिया जाये।

दूसरी चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि यह ठीक नहीं है कि अगर कोई पहले मंत्री थे और आज नहीं हैं तो उन को उन प्रोजेक्ट्स में भेज दिया जाये जैसे कि श्री मालवीय को जगह दिलाई गई। जिस तरह से जो गाय दूध नहीं देती उस को गोसदन में भेज दिया जाता है उस तरह से जो मिनिस्टर हार जाय या पार्लियामेंट का मेम्बर हार जाय उस को इस तरह से नौकरी दे कर पोलिटिकल गोसदन में नहीं रक्खा जाना चाहिये क्योंकि उद्योगों के लिये वह कुछ नहीं कर सकता। आज जो आप उन को कहीं का चेयरमैन बना देते हैं, कहीं का मैनेजिंग डाइरेक्टर बना देते हैं, कम से कम इस तरह के पोलिटिकल गोसदनों को आप मेहरबानी कर के बन्द कर दीजिये। श्री पन्त से भी मेरी यही प्रार्थना है।

इस्पात तथा भारी इंजनियरिंग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्ण चंद्र पंत) : अगर गाय दूध न दे और जो सदन में भी न भेजी जाए तो गो हत्या की जा सकती है ?

श्री कंवर लाल गुप्त : मंत्री महोदय ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। मेरी पार्टी की मांग जो है वह मैं बताता हूं। मैं हत्या करने के पक्ष में नहीं हूं। एक गाय के ऊपर जिस को गो सदन में भेजा जाता है, गवर्नमेंट के स्टेटिसटिक्स हैं, कि एक साल में एक सौ रुपया ज्यादा खर्च आता है। जो साधारणतया उस पर खर्च आता है, जो खाद आदि के रूप में मिलता है, उस सब का हिसाब लगा कर देखा जाए तो एक सौ रुपया साल का ज्यादा खर्च आता है। एक हजार गायें रखी हों तो एक लाख रुपया उनके लिये एक साल के वास्ते चाहिये। लेकिन ये जो पोलिटिकल गाय या सांढ़ हैं उन के ऊपर दस हजार रुपया महावार खर्च आता है जितना खर्चा एक हजार गायों पर सालाना आता है उतना एक इस पोलिटिकल गाय या सांढ़ पर आता है। श्री मालवीय को आपने मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया और उन पर एक हजार गायों जितना खर्च आता है। मैं नहीं चाहता हूं कि उनको मारा जाए, उनकी हत्या की जाये। मैं तो यही चाहता हूं कि ऐसे आदमियों को रखा जाये जिन को उस चीज के बारे में अच्छा खासा ज्ञान हो। लेकिन आप करते क्या हैं? कोई आई० सी० एस० अफसर रिटायर होता है तो उसको आप उधर लगा देते हैं। ये आई० सी० एस० अफसर भी बड़े खतरनाक जानवर हैं। ये भी उसी तरह की चीज है। इनको भी आप रिटायर होने दीजिये। नए ब्लड को आप सामने लाइये, उनको आप ट्रेनिंग दें और जिस अफसर को जिस तरह का ज्ञान हो, उसको उस तरह के काम पर लगाइये। केवल सिफारिश नहीं चलनी चाहिये और न ही पोलिटिकल कंसिड्रेशन इस में आनी चाहिये। जो काम करे उसको आप इनाम दें, उसको आप आगे लायें और जो न करे, उसको आप हटा दें।

आपको एक माडल एम्प्लायर भी बनना चाहिये। कई जगहों पर पब्लिक सैक्टर में गड़बड़ियां चल रही हैं। आपको एक आदर्श सामने रख कर चलना चाहिये। प्राइवेट सैक्टर को पता चलना चाहिये कि सरकार कितनी अच्छी तरह से बिहेव करती है, उसको सरकार से प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिये। लेबर का भी उसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिये। आहिस्ता आहिस्ता ऐसा भी किया जा सकता है। मैं तो कहूंगा कि अगर किसी को आप बोनस देते हैं तो उसे आप शेयरों के रूप में दें ताकि वे लोग भी उसमें हिस्सेदार बन सकें और हिस्सेदार बन कर वे उस उद्योग को अपना समझें। इस तरह का आदर्श सरकार को अपने सामने रखना चाहिये।

रिपोर्ट में कहा गया है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। इन्होंने 1968-69 का फिगर दिया है। इन्होंने इस साल 53 करोड़ का माल एक्सपोर्ट किया और 93 करोड़ का माल इम्पोर्ट किया। जो एक्सपोर्ट है वह इम्पोर्ट से कम है। मैं चाहता हूं कि आसपास के जो देश डिवेलेप कर रहे हैं, उन में आप मार्किट चलाइये। आप यू० के० और दूसरी जगहों को छोड़ दें। जो आसपास के देश डिवेलेप कर रहे जहां शहर बन रहे हैं, जहां बहुत बड़ी-बड़ी योजनायें बन रही है, उन देशोंमें अपने आदमी भेजिये, वहां पर आपके माल की ज्यादा मांग हो सकती है। मैं समझता हूं कि अगर उसके लिये कोशिश की जाए तो हमारी जो अनयूटिलाइज्ड कैपेसटी है उसका भी हम काफी मात्रा में इस्तेमाल कर सकते हैं।

जो हमारा कास्ट आफ प्रोडक्शन है यह भी बहुत ज्यादा है। आपने टाप हैवी एड-मिनिस्ट्रेशन रखा हुआ है। मिसमैनेजमेंट भी है। टारगेट्स भी पूरे नहीं होते हैं। इस

[श्री कंवर लाल गुप्त]

वास्ते कास्ट को घटाने की कोशिश होनी चाहिये । आप मालूम करें कि किस तरह से इसको घटाया जा सकता है। अगर इस कास्ट का मुकाबला दूसरे देशों से किया जाये तो फी टन वह बहुत ज्यादा है। खुद रूस का डैलीगेशन यहां आया था। रूस ने जो प्राजेक्ट लगाई है उसके बारे में भी उस डैली-गेशन ने बड़ा डिससैटिसफैकशन शो किया है। यह ठीक नहीं है। इस को ठीक किया जाना चाहिये । मैं मांग करता हूं कि जो रिपोर्ट रशियन डेलीगेशन ने दी है उसको सभा पटल पर रखा जाये ताकि लोगों को मालूम हो कि रूस जो हमारी सहायता कर रहा है इसके अन्दर, उनके क्या विचार हैं प्रगति के बारे में। रूस के जो एक्सपर्ट आये थे, मैं कहता हूं कि उनकी जो रिपोर्ट है उसको छिपाया न जाये बल्कि उसको सदन पटल पर रखा जाए ताकि लोगों को मालूम हो कि कहां क्या गड़बड़ है । गड़बड़ को छिपाने से उसको दूर नहीं किया जा सकता है ।

सिद्धान्त रूप में मैं चाहता हूं कि पब्लिक सैक्टर बढ़े। मैं यह भी चाहता हूं कि कम्पीटीशन की भावना भी पैदा हो। लेकिन माइनर आप्रेशन से काम नहीं होगा। ड्रास्टिक स्टेप्स आपको लेने होंगे। नए मंत्री जो आए हैं, उनको एक साल का समय कम से कम मिलना चाहिये काम करके दिखाने के लिये। इन शब्दों के साथ जो मांगें हैं इनका समर्थन तो मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये सरकारी मांगें हैं। लेकिन अगर पुनाचा साहब की होती तो मैं समर्थन कर देता ।

श्री गा० शं० मिश्र (छिन्दवाड़ा) : सभापति महोदय हुआ मैं इस्पात तथा हैवी इंजीनियरिंग मंत्रालय की मांगों का समर्थन करने के लिये खड़ा हूं। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय उन सुझावों पर ध्यान दें।

ऐसी कई चीजों का उत्पादन हो रहा है जैसे लोहे की पत्तरें, चद्दरें जिन पर चार सौ से एक हजार रुपये टन तक का ब्लैक मार्किट होता है। पिग आयरन पर भी ब्लैक मार्किट होता है। इसी तरह से कुछ चीजें हैं जो हमारे यहां ज्यादा बनती हैं, जैसे रेलें हैं, जिन का कहीं मार्किट नहीं है हिन्दुस्तान के बाहर। हिन्दुस्तान में जितनी रेलों की डिमांड है उससे चौगुनी रेलें बनती हैं। उनका स्पेसि-फिकेशन ऐसा होता है कि हम उनको एक्सपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमें चाहिये कि हमारा यह मंत्रालय स्टील में जिस चीज का भी प्रोडक्शन होता है उसका नियंत्रण करे । ऐसी चीजें बनाई जायें, ऐसा प्लानिंग किया जाये ताकि जो भी चीजें बनाई जाएं उनकी बिक्री हो, हिन्दुस्तान के अन्दर की जो मांग है, वह भी पूरी हो और एक्सपोर्ट भी उन चीजों का हो सके। आवश्यकतानुसार स्पिसिफिकेशन तब्दील किए जायें।

दरअसल इस मंत्रालय का ज्यादा नियन्त्रण होना चाहिये प्रोडक्शन पर। आज हम पिग आयरन एक्सपोर्ट करते हैं। स्ट्रक्चरल्ज़ पर हमारे कुछ बंधन हैं। होना यह चाहिये कि पिग आयरन से हम स्ट्रक्चरल्ज बना कर, फिनिश्ड गुड्ज बना कर, तैयार माल बना कर उसको बाहर भेजें ताकि हमें अधिक रुपया मिल सके। पिग आयरन का जो तैयार माल बनाया जाता है उसके कारखाने पब्लिक और प्राइवेट सैक्टर में हमें ज्यादा से ज्यादा चलाने चाहिये ।

हिन्दुस्तान स्टील में जो फिजूलखर्ची चल रही है, उसकी तरफ भी आपका ध्यान जाना चाहिये । इन सब कारखानों में आज जो डायरेक्टर्ज हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अफसर हैं, वे मनमाने तौर पर दुनिया भर में घूमते फिरते हैं। उन पर मंत्रालय का सही मानों में सीधा कोई नियन्त्रण नहीं है। एक मैं मिसाल देना चाहता हूं । जब दुर्गापुर कारखाने में झगड़े चल रहे थे तब एक बहुत बड़े अफसर श्री चंडी वहां से भागे, यू० के० वह चले गये, इंग्लैण्ड वह चले गये । मंत्रालय की तरफ से

उनको तार दिया गया, केवल दिया गया कि वह वापस आ जायें। उन्होंने उस बात को ठुकरा कर, उन आदेशों का पालन न करके, अमरीका जाना पसन्द किया और वह अमरीका चले गये। ऐसे जो लोग हैं और जो बहुत ज्यादा असरदार भी हैं, सही मानोंमें ऐसे लोगों पर कुछ तो मंत्रालय का नियन्त्रण होना चाहिये, कुछ तो उनके खिलाफ कार्रवाई मंत्रालय को करनी चाहिये।

श्री नरदेव स्नातक (हाथरस) : लौट कर आ गए हैं या नहीं ?

श्री गा० शं० मिश्र : मेरे खयाल से आ गये हैं।

जब मीटिंगें होती हैं तो क्या होता है ? आफिस इनका कलकत्ता में है। जहां स्टील प्लांट है वहां से ये लोग रोज हवाई जहाज से आते हैं। मीटिंग यदि चार रोज तक चलती है तो सुबह वे हवाई जहाज से आते हैं और शाम को हवाई जहाज से वापिस चले जाते हैं। इसी तरह से दूसरे, तीसरे और चौथे रोज भी वे आते हैं और चले जाते हैं। इस तरह से यह जो फिजूल खर्ची होती है, इस पर रोक लगनी चाहिये।

आप यह भी देखें कि इनके बड़े बड़े गैस्ट हाउसिस हैं। उन गैस्ट हाउसिस को इस तरह से सजाया गया है कि हमारे किसी मंत्री के बंगले को भी उतनी अच्छी तरह से नहीं सजाया गया है। इनकी आखिर क्या जरूरत है ? इनको बन्द किया जा सकता है।

इन सब के यहां लायजन अफसर हैं। इतना बड़ा मंत्रालय यहां पर है। ऐसी अवस्था में इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें दे कर इन लायजन अफसरों को रखने की क्या जरूरत है ? इन पर भी कुछ बंधन लगना चाहिये।

मैं मंत्री महोदय से यह भी प्रार्थना करूंगा कि कभी कभी बगैर बताये हुये और अकस्मात उनको इन कारखानों का मुआयना करने के लिये जाना चाहिये। अगर उन्होंने ऐसा किया तो और भी बहुत सी चीजें उनके सामने आयेंगी।

जहां तक वितरण का सम्बन्ध है, उसकी जो पद्धति है वह मंत्रालय से कंट्रोल नहीं होती है, नियन्त्रित नहीं होती है। ज्वायंट प्लांट कमेटी जैसी कुछ अजीव सी चीजें बना दी गई हैं जहां भ्रष्टाचार का बोलबाला है। कुछ ऐसा भी प्रोडक्शन होता है कि जिस की तादाद दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है और वह है डिफैक्टिव माल। डिफैक्टिव माल जो तैयार होता है उसका वितरण वहां से सीधा होता है। उसमें भाई भतीजावाद चलता है। अपनों को कम पैसों में ज्यादा माल देने का तरीका भी वहां चल रहा है। वजन करने में भी गड़बड़ी होती है। परचेजिज़, ढुलाई और आयरन और तथा लाइम स्टोन के रेंजिंग में भी भ्रष्टाचार है। यही स्थिति वेमेंट में भी है। एनेलिटिकल लैबोरेटरी में भी भ्रष्टाचार है; वहां पर लो ग्रेड माल को हाई ग्रेड बना दिया जाता है। इन सब बातों पर मंत्रालय का सीधा नियन्त्रण होना चाहिये। मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि एक ऐसा सेल बनाया जाये, जो इस तरह की चोरियों को पकड़े। आज हालत यह है कि जो शिकायतें की जाती हैं, उन की बिल्कुल उपेक्षा की जाती है। पब्लिक सैक्टर पर सरकार का नियन्त्रण होना चाहिये। मैं आशा करता हूं कि श्री पुनाचा, श्री पन्त और श्री शफी कुरैशी इस बारे में काफी दिलचस्पी ले कर इस स्थिति को बहुत जल्दी दुरुस्त करेंगे।

स्टील के इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट के आंकड़ों को देखने से अफसोस होता है कि हम ने जितनी प्रगति की है, उस का क्या अर्थ है। इम्पोर्टस को भी नियंत्रित करना चाहिये।

इस बात की तरफ भी ध्यान देना चाहिये कि मजदूरों के साथ हमारे सम्बन्ध अच्छे हों, ताकि अधिक काम हो और उत्पादन में वृद्धि हो।

14.52 hrs.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

आज हम 1,300 करोड़ रुपये की लागत से देश में 6 मिलियन टन लोहा बना रहे हैं। बोकारों पर हमारा 1,100 करोड़ रुपया खर्च होगा और वहां पर 3 से 4 मिलियन टन तक उत्पादन होगा। इसका परिणाम यह होगा कि यद्यपि हमारा लोहा दुनिया में सब से ज्यादा महंगा है, लेकिन उस को और ज्यादा महंगा करना पड़ेगा। पहले लोहे का भाव 640 रुपये प्रति टन था। इन चन्द वर्षों में बढ़ते बढ़ते वह 1200 रुपये प्रति-टन तक पहुंच चुका है। बोकारो में लोहे के बनने के बाद उस के घाटे की पूर्ति के लिये पब्लिक सैक्टर के लोहे की कीमत और बढ़ानी पड़ेगी। उस की कीमत 1500, 1600 रुपये प्रति-टन तक पहुंच जायेगी और तब एक्सपोर्ट सम्भव नहीं होगा। इस लिये मंत्रालय बोकारो के सम्बन्ध में जल्दी न कर के उस पर फिर से विचार करे और देखे कि इस सम्बन्ध में कहां तक दुरुस्ती की जा सकती है, ताकि उस में हमारा इनवेस्टमेंट कम हो।

इन शब्दों के साथ मैं इन मांगों का समर्थन करता हूं।

14.53 hrs.

RE: MESSRS. SYNTHETICS AND CHEMICALS

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, unfortunately you were not in the Chair in the afternoon when we met and we had to trouble Shri Gowd. You will remember, Sir, that you asked the Minister of Parliamentary Affairs to accept a Short Notice Question regarding the controversy that is going on about the sole selling agency of Messrs. Synthetics and Chemicals being given to Khilachands. Because the meeting is taking place today at 4 p.m. and another meeting at 4 O'Clock tomorrow, I would request you, Sir, to move the Minister concerned to make a statement.

MR. DEPUTY-SPEAKER : If I remember correctly, when Shri Madhu Limaye, Shri N. K. Somani and others raised it on the floor of the House, I said that this is a serious matter because LIC has invested quite a big amount in this enterprise. Naturally, the House is concerned with it, in so far as it is a public investment. So, I supported the plea and, if I remember correctly, I said that it would be a good thing if the Minister of Parliamentary Affairs contacts the concerned Minister so that the Minister could give a statement, giving all facts. That is what I said that day. It shall find out just now what the position is and then I will say something about it.

14.55 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*
MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING —*Contd.*

SHRI SRINIBAS MISRA (Cuttack) : Mr. Deputy-Speaker, Sir, the report presented by the Ministry appears to be misleading and that designedly so. In this report the Ministry perhaps seeks to take pride in the fact that our exports of iron and steel are increasing. The names of various countries to which our exports are being made are also mentioned with pride. But look at the figures supplied by the Ministry and you will find that these exports are at the expense of the internal needs or demands of the country.

SHRI R. D. BHANDARE (Bombay Central) : On a point of order, Sir. The hon. Member has said that the report is misleading and designedly so. By this he is actually imputing motives.

SHRI SRINIBAS MISRA : I stand by it. I will prove it from the report.

SHRI R. D. BHANDARE : Sir, misleading is for the purpose of misleading the House. That is most objectionable.

MR. DEPUTY-SPEAKER : If the hon. Member making the statement si ready to substantiate it, how can you prevent him ? It is his view after going through the report.

SHRI SRINIBAS MISRA : I am proving it.

SHRI R. D. BHANDARE : You are too lenient.

SHRI SRINIBAS MISRA : The table given at page 5 gives us an imaginary picture of things to come in 1973-74 and 1978-79. From this it will be seen that domestic demand of finished steel will be 7.12 and 10.97 million tonnes respectively and exports of finished steel will be 1.30 and 1.80 million tonnes respectively but at the same time at the end of the table it is shown that the gap would be of 2.7 and 6.42 million tonnes respectively. This would show that actually these are not exports; these exports are made at the expense of the internal demands of the country.

There is nothing to be pleased at the exports and the rising figures of exports. It is not that there is a surplus in the country of iron products and they are being exported. Perhaps in our craze for having more and more foreign exchange, we will be willing to sell anything for foreign exchange, as it appears, even ourselves. We are doing that every minute.

Then, it says about the existing capacity—main producers and secondary producers—and availability at 90 per cent utilisation. Where on earth do you think you have got your technology from so as to arrive at availability at 90 per cent utilisation ? In the next sentence you say that the corresponding global figures are 80 to 85 per cent. Do you mean to say that our production, our technology and our management are so excellent that we will go 5 per cent over the global figure ? For everything we are borrowing from outsiders. For every little defect we are consulting outsiders—some Torsch from somewhere, some body from the USSR or from America or from other countries. We are seeking their help in every titbit and still we take we will have 90 per cent utilisation whereas the global figure is 80 to 85 per cent. Even taking the utilisation at 90 per cent, our gap in 1978-79 in finished steel will be 6.42 million tonnes and in pig iron it will be 2.98 million tonnes.

Another rosy picture has been given at page 7. They include certain programmes and perhaps the Ministry wants to show that when those programmes mature our internal demands will be fully met and we will have some surplus for export. In this table for Bokaro 1.36 million tonnes of finished steel have been fixed and 1.16 million tonnes of pig iron have been fixed for 1973-74 and 3.22 million tonnes of finished steel has been fixed for 1978-79. These are all imaginary figures. It does not cost anything to put something into those imaginary works which have not come into existence.

15 hrs.

Much has been said about Bokaro steel plant. Anybody visiting Bokaro steel city will not find a scrap of steel in Bokaro now. All the steel that is found in Bokaro is taken from outside. Perhaps, the Ministry is aware that all the machinery that has come for the Bokaro steel plant is lying not in cold storage but in warm storage. If this still continues, what we will get is, it will get roasted and we will have to invest more money in producing it. Whatever Engineers and personnel there are, you must be meeting their expenses. The whole paraphernalia is there except the steel plant itself. Nothing has been installed. If you search the whole steel city, not a single machine has been put in place. It is said, they have come but they are not put in place. We have, again and again, demanded in this House that the Minister should give us a firm date when it will come into production. The date is shifting. Even now the Minister is not able to say what is the firm date when it will come into production. Perhaps, the Minister feels helpless in such a situation, in such a vicious circle, in Bokaro and we have our own doubts whether it will come into production in 10 years.

In the circumstances, you will find that the figures of 1973-74 to 1978-79 are all imaginary, a rosy picture which, as I stated earlier, is designed to give a wrong picture to the House. Mr. Bhandare will, perhaps, realise that, from these figures, it is amply proved that these are imaginary figures and they are not going to materialise very soon.

SHRI R. D. BHANDARE : You are repeating with vengeance.

SHRI SRINIBAS MISRA : Why do you object to it ?

Then, I will come to another point. The Government is swearing by public sector and much of the finance of this country

[Shri Srinibas Misra]

is being invested in giant projects in public sector. What is the figure now ? The hon. Minister of State was very stoutly defending the expenses and the cost obtaining in public sector projects. His argument was that the size and the inputs are so much that the production cost must be high. He said that the production cost compares favourably with private sector. But still there are losses because the input is high ..

THE MINISTER OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI C. M. POONACHA) : The Capital, not inputs.

SHRI SRINIBAS MISRA : You say, the capital is high. The Ministry should take into consideration what is really a viable and economic unit. Sometimes, dwarf unit is uneconomic and giant unit is also uneconomic. This must be taken into consideration. Without taking that into consideration, if you put all your eggs in one basket and, if that basket somehow breaks, all the eggs will break. You have not taken that into consideration.

About investment, what is the proportion as between private sector and public sector ? 41 per cent of the basic ingots, even now after so much investment in public sector steel projects, is produced by private sector. So far as electric ingots are concerned, 41 per cent is produced by public sector. It is just the reverse. Curiously enough, about the finished product, 55 per cent is still produced by the private sector. What is the investment in the public sector and what is the investment in the private sector ? As compared with our investment, even now the private sector supplies 55 per cent of the total production of the finished steel in the country.

I have one or two more points to make...

SHRI C. M. POONACHA : Could my hon. friend quote those figures? I do not think that he is correct in saying that 55 per cent is being produced. Could he kindly quote from that misleading document which he seems to have ?

SHRI SRINIBAS MISRA : Not misleading calculations. In arithmetic, nobody can mislead. It can be checked up.

MR. DEPUTY-SPEAKER : Interpreting the figures in a particular way is possible.

SHRI SRINIBAS MISRA : Please see Appendix III, page 50—Production of Finished Steel. There you have given Tisco and Iisco—these are private firms. Then comes Mysore. Myosre is not a Union concern. Then come Rourkela, Bhilai and Durgapur. The total of Tisco and Iisco is 1497, *i.e.*, about 1,500 thousand tonnes by the private sector. And what does the total of public sector minus Mysore come to ? It comes to about 1,900 thousand tonnes. Therefore, it comes to 55 per cent of the finished product. Please also look at the 'Total (Main Producers)' and 'Total (Other Producers)'. The 'Grand Total' is 4,435 thousand tonnes. Out of that, the figure of the public sector can be seen—you add up 716, 840 and 332 thousand tonnes. So, the private sector comes to 55 per cent. You may calculate or you may ask your Secretary to calculate. This is the figure. I have just calculated.

Regarding Hindustan Steel, some excuses have been found out by the Minister of State. It is perhaps the worst to throw the blame at the doors of the workers who are working there, to say that they are the main cause for these losses. Government ought to be a model employer. Public sector undertakings ought to be the spheres of model employment. But, instead of being the model employer, the Government is trying to put all the blame for their mismanagement at the doors of the workmen. Here I would say that it is unfortunate that, regarding Durgapur, such a statement should have been made in the Report itself, *i.e.*, on page 27; it should not have been made; at least it is in bad taste, whatever else it may be.

What other things are there regarding Hindustan Steel ? Agreements are being waved. They have said on pages 20 and 21 :

> "The Company has taken a major step in diversification with the execution of an agreement with M/s. Tor Isteg Steel Corpn. of Luxembourg for the production of cold twisted ribbed bars ......"

> "The question of strengthening the Bureau further with the assistance of the Government of the USSR is at present under consideration."

All these are being waved before us that they are going to do this and that. But the present performance is an indication of the performance to be made in future.

I oppose these Demands.

THE MINISTER OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING (SHRI C. M. POONACHA) : I thank the House and particularly the hon. members who participated in this debate. They have given an objective assessment of the working of this Ministry and have also made some constructive suggestions. Views were not wanting as regards certain ideological approaches too. I do not want to go into this matter, but before I come to certain specific points, I would perhaps like to clear one or two wrong impressions that seem to have prevailed upon some hon. members of this House and particularly on my hon. friend, Shri Srinibas Misra, who spoke last. As regards the figures that we have furnished in respect of finished steel, ingots steel and pig iron—all these you will have to take into account in arriving at a conclusion regarding the production capacity of the various steel plants private or public. My hon. friend knows it very clearly that TISCO capacity in terms of ingots steel is—2 million tonnes and IISCO—1 million tonnes while all the other public sector steel plants *viz.*, Rourkela, Bhilai and Durgapur produce 5.9 million tonnes. 55-45% ratio can very well be calculated. Apart from that, the question is that these are two integrated steel plants. The integrated steel plants like the composite textile mill have a range of production lines. But we have at the same time other units like the re-rollers, foundries who require the raw material and it is somebody's job—it should be somebody's job—to provide this raw material. Here is Hindustan Steel providing this raw material to the maximum number of units that engage in finished products. The maximum quantity of ingot steel and pig iron is being supplied and to that extent Hindustan Steel is not using in its own finishing plant which may be profitably done and then make money on it. But there are several hundreds of these units which have to be looked after and Hindustan Steel while producing the most essential lines of finished steel material is also a supplier of raw material in a substantial way and in very substantial quantities to various re-rollers and foundries and what not and in this respect Hindustan Steel is fulfilling a function which is very essential to the economic prosperity of this country Let us not judge Hindustan Steel by the one single table that is given here. If we take a comprehensive view of the entire information furnished here you will come to know that Hindustan Steel, in so far as its production capacity is concerned, has been catering its own finished lines and also various units that are established in this country with regard to finished steel materials, re-rollers and what not.

श्री अब्दुल गनी दार (गुड़गांव) : फिर 122 करोड़ रुपये का नुकसान क्यों है? अगर आप पब्लिक सैक्टर में इतना कुछ कर सकते हैं, तब तो फायदा होना चाहिए, नुकसान क्यों होता है?

[شری عبدالغنی ڈار (گڑگاؤں) : پھر 122 کروڑ روپیے کا نقصان کیوں ھے - اگر آپ پبلک سیکٹر میں اتنا کچھ کر سکتے ھیں تب تو فائدہ ھونا چاھئے - نقصان کیوں ھوتا ھے -]

SHRI C. M. POONACHA : He was explaining. I thought I need not go over it again. He was explaining the particular point as regards the pricing and profitability of the steel plant, particularly in so far as assessment of the profit. Taking into consideration the block capital, our overheads are about Rs. 176 more per tonne than what is calculated on the basis of the Tariff Commission's recommendations providing the basis for fixing the steel prices where they had taken only about Rs. 1,100 as the block capital while our capital block is Rs. 2.500. In this calculation the extra overhead charges that come upon HSL is to be extent of Rs. 176 and further more it has been added while we have been subjected to a straight depreciation of 7% per annum on three shift basis which again has added another Rs. 20 or Rs. 26 per tonne.

These are the various calculations as regards the financial performance and explanations have been given to Parliament from time to time. There is a certain pattern which has been laid down, and certain heavier

[Shri C. M. Poonacha]

overhead charges compared to other units. But, I am not in the least wanting to draw any individious comparisons; but would like to place the facts as they are. For the time being there is a heavier rate of deprecition. Now, take for example, this rate of 7%....

SHRI ABDUL GHANI DAR : I have great respect for the hon. Minister. But I would like to ask one question. Is it not a fact that due to defective production certain orders placed with public sector were cancelled, and that resulted in huge losses?

SHRI C. M. POONACHA : I would like to have from my honourable senior colleague of this House some specific instances and I will certainly take them up. He can bring up such cases. Let us understand the position. As regards these calculations, I may say, the Hindustan Steel at the moment is not in an advantageous position. Perhaps at the rate of 7% depreciation, after 14 or 15 years the written down value will be such that the returns of HSL earnings would be much more profitable and, as it happened in the case of the other older steel mills I am sure steadily and gradually these public sector steel mills also will be able to give a better account of themselves at the given time. But at the moment I am not well-pleased, and I am certainly conscious of the fact that Hindustan Steel is losing. It has lost Rs. 40 crores last year. And the next year's prospects are that there would be about Rs. 15 to 16 crores of loss. This is just an estimate and it is not something encouraging. References have been made to this aspect that in these public sector organisation such heavy sums of money have gone as capital and that the country's resources are locked up. I would like to explain certain special factors which this House should take into consideration. It is true that capital has been invested. It is true that we have sustained certain losses. Rs. 162 crores is the cumulative loss up till today. I agree there. But let us also take into consideration the other side of the coin. Take Bokaro for instance. Some friends were suggesting that we should now not go beyond the 1.7 million stage. I don't agree with that. We can see the figures with respect to Bokaro project in comparison with the other three steel plants where we had collaboration arrangement with friendly countries where the steel plants were intsalled on a turn-key basis. Now so far as Bokaro is concerned I can give figures. As regards equipment, the figure is Rs. 2,76,800; 64 per cent of the equipments will be made in our country. This is for the first time going to be designed and made by our own technicians and by our factories. As regards structurals....

SHRI S. KUNDU (Balasore) : I will be made. But when will it be supplied ? That, nobody knows....

SHRI C. M. POONACHA : I am coming to that. Please at least have this satisfaction.

This country has come to a stage to claim that it could make this. Do you mean to say that we would ever have made these, unless we had gone the way we had gone. (*Interruptions*).

SHRI S. KUNDU : At what cost ?

SHRI C. M. POONACHA : As regards structurals, out of 2,36,977 tonnes, 93 per cent are going to be made and fabricated in this country. The achievement is not of a mean order. As regards refractory materials, out of 2,12000 tonnes. 97 per cent are going to be made indigenously. This shows how we are making steady progress towards self-sufficiency, 'indigenousation' and self-help in acquiring knowledge and technique as regards steel plant construction in this country. HEC, MAMC, Civil Engineering and Designs Bureau of HSL, are all now organised to a level where we can hopefully look forward for the construction and installation of the plant from out of our own effort, our own initiative and our own technical know-how. This is the stage to which we have to go ahead. Take for example, it is very easy for us to say : Why don't you do that ? It cannot be done for nothing. Certain amount of losses is inherent in this big scheme and if at all a country can claim to have economic strength, it is judged by the way it can handle basic industries in the country and the way it goes ahead with confidence about basic, sustaining industries that are required for the development of the nation's economy.

Now let us project our mind and attention to the report of the Steering Committee. My friend Shri Somani referred to the point—he is not here now—that we had projected our views and thinking on certain studies made by the Council of Applied Economic Research that the demand of this country is going to be somewhere of the order of 20 million tonnes in about 12-15 years. Now we are in a position to have an installed capacity of about 9 million tonnes—from 9 million tonnes to 20 million tonnes. That is to say, even if we think in terms of three or two million tonnes unit, it will mean another 5 or 6 steel plants in the country. For another 5 or 6 steel plants, the know-how is within the country. The technical competence is within this country; the trained personnel, technicians and technocrats are all going to be in our country. It should be a day of pride so far as India is concerned when the sixth, seventh or eighth steel plant will be wholly indigenous and towards this direction we are now marching ahead.

श्री महाराज सिंह भारती (मेरठ) : जब इतनी बड़ी ज़रूरत है तो बोकारो के बाद वाला प्लान्ट आप क्यों नहीं प्लान कर रहे हैं ? उस से पीछे क्यों हट रहे हैं ?

SHRI C. M. POONACHA : That we are doing. If you have studied the Fourth Plan, you would have known something about it. In this regard, you have to do ever so many other things. Not that the CEDB of the HEC and the rest of the technical institutions and Bureaux can by themselves do everything. We are negotiating with friendly countries for certain specialised know-how and licences. As regards blast furnace, we are negotiating with USSR. As regards to the rolling mills, we are negotiating with America. For the LD converter, we have already a licence with Austra. For coke ovens, we are again discussing with the USSR. As regards the pelletisation plant, we are discussing with the USSR. For continuous casting, which is going to revolutionise the very process of steel-making in this country, we have a collaboration with Russia. With all these lines of specialised items of manufacture, we could attain a stage where we will be self-sufficient and will be able to go ahead and think in terms of design, construction and manufacture entirely on our talent and our resources.

We have not yet been able to take up the fourth steel plant programme. Shri Anbazhagan was referring to the Salem Steel plant. In that connection, he referred to a statement on page 7 of this report in which we have said that in 1973-74, we have projected certain demands to develop and also explained the capacities we have, that is to say, by that time, the total capacity in our existing units with certain exapnsion carried out and certain technological improvements effected in the process of manufacture, we will reach a stage of 9.4 million tonnes which at 90 per cent availability should be about 8.46 million tonnes. But when we go to the fifth plant, 1978-79, we should reach a stage where the demand would be 13.74 million tonnes which at 90 per cent availability would be 12.37 million tonnes, which means that the gap will be about 3 million tonnes. That is shown as new steel plant 2.38 and pig iron 1.23.

THE MINISTER OF FOREIGN TRADE AND SUPPLY (SHRI B. R. BHAGAT) : Include exports also.

SHRI C. M. POONACHA : This is as regards home demand. Then we are adding exports and to that extent, the capacities will have to be created, that is to say, the next stage, for having new steel plants in the country to meet the additional demand that would be generated; probably in the Fifth Plan period we will reach that stage. During the Fourth Plan period, we have got to be ready with all the studies, surveys and project reports and all the rest of it. In this particular regard, now the Steering Committee has given its report and the Planning Commission is now studying it; after the necessary studies have been completed, we would be in a stage to take a decision as to the location, which would be the ideal location, taking into account all the requirements, raw materials, energy, water and what not. A technical body would go into these things and take a final decision. At the moment, we are not in a position to indicate which would be the exact location of the next steel plant.

श्री क० ना० तिवारी (बेतिया) : मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं । आल टाइप्स आफ शीट्स, जिनकी इस देश में इतनी डिमांड है,

[श्री का० ना० तिवारी]

उसे आप क्यों नहीं बनाते हैं? उस डिमांड को आप क्यों नहीं पूरा करते हैं?

SHRI C. M. POONACHA : Reference has been made to the non-availability of certain scarce categories of steel. As the House is aware, from 1967 steel has been completely decontrolled, but a sort of informal control is being exercised through the Joint Plant Committee which, along with the main producers of steel, has a working arrangement. In arriving at this working arrangement, there is the Steel Priorities Committee which fixes priorities. With regard to flat products and certain special items of steel, the Priorities Committees would fix the priority as would be required by certain essential sections of the administration, such as defence, railways, the DGTD and the rest, and the small-scale industry. Taking into account their demand, certain allocations will have to be made on a priority basis. After making this priority allocation, what remains goes to the open market for sale. In that, I realise the point that there is scarcity, but with the expansion of Rourkela plant, where the flat production capacity has been increased substantially and where we are now having electrolytic tin-plate section, a plate mill and a galvanised sheet mill, and the cold-rolling section, it should be possible for us to meet the demands in the country as regards flat products.

So far as pig iron is concerned, this year, I am confident that the demand would be fully met. The demand as assessed is somewhere near one million tonnes and we would be in a position to meet substantially this one million tonne demand for pig iron. As regards billets, the demand is roundabout one million to 1.1 million tonnes. Our production capacity is about 0.9 million tonnes. We have a heavy programme of export commitment and we have got to honour the export commitment. It is our intention that we should honour this export commitment and, at the same time, try to meet the internal demands. We have made certain special arrangements and I hope that we will be able to meet the billet demand inside the country in a substantial manner. We should be able to meet about 80 to 85 per cent.

As regards, flats, there is scarcity and we are making every effort to see that we are in a position to meet the demand, as regards these scrace items.

I would like to mention briefly about the steel plants. As regards Bokaro and the other three main plants, in the series of things, our foreign exchange component was of the order of 25 per cent. Some hon. Members referred to a point the other day that even when you say in percentages that you would be meeting 64 per cent of equipment and 90 per cent of structurals, this and that, your import element costs much more and therefore your foreign exchange component is very high. As regards the other three steel plants, the foreign exchange component was of the order of about 45 per cent. As regards Bokaro, it is going to be 25 per cent. The Russian credit that has been offered is about Rs. 160 crores to Rs. 167 crores. I think within that, it should be possible for us to adjust and that would be just 25 per cent of the foreign exchange element that would be required for Bokaro steel, a very big project which we have in view.

MR DEPUTY-SPEAKER : Two minutes more.

SHRI C. M. POONACHA : I realise the House has not much time to spare. I should have certainly liked to—

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON) : There is no need to ration the time; after all, you are going to guillotine the Demands.

MR DEPUTY-SPEAKER : It is not only a question of your Ministry. Members would like to have the Ministry of Health also touched. I cannot keep that out. It is very difficult. Steel Ministry had four hours at least; but others hardly get that much.

SHRI C. M. POONACHA : I would very briefly refer to one or two other points. It was mentioned that Government should be an ideal employer. I would have liked to know in what respect we have failed in this regard, as to where we have not been an ideal employer. Take, for example, these very three steel plants, and

what is going to be in Bokaro also. It was almost a charge levelled against this Ministry that we have provided all the housing facilities and other amenities like water, electricity, health, school and everything. Therefore, you havei ncurred a higher capital cost. On the other hand, some people say, you have put up everything and provided all the facilities and amenities to labour even before you start production. Between the two, Government has to strike a *via media*, as ideal employer. When steel mill workers come to work in the plant, they should have all the necessary amenities. Therefore, Government have provided all the amenities. I hope the House would agree that steel plant workers have a better deal today than anybody else compared to other sectors of industry. I can confidently claim that. I have figures to show it. In Durgapur, the pay of the ordinary worker is somewhere about Rs. 250 including bonus and fringe benefits.

SHRI RANDHIR SINGH : Illiterate labour gets that much ?

SHRI C. M. POONACHA : Yes. But he is working on a three-shift basis and he performs a difficult task. This is all tied up with certain production levels. Let us see the productivity in Durgapur, I am taking Durgapur because it has been highlighted in certain discussions in this House. The productivity at the ingot stage was 68 tonnes per man-year in 1966-67. It dropped down to 50 tonnes in 1967-68 and to 47 tonnes today. This explains the position which has got to be tackled. On this ideology and principle that Government should be a model employer in the matter of paying labour, if productivity is consistently dropping, these two things will not marry. The result is, Durgapur has incurred a loss of Rs. 18 crores in the previous year and a loss of Rs. 18 to 19 crores this year. Next year it will incur a loss of Rs. 15 to 16 crores. At this rate, it cannot sustain the continuous losses and it will work to its disadvantage. Therefore, we, the employers, the leaders of the labour unions and Government—everybody—will have to put their heads together and see that while labour gets all its due under the law, responsibility to do work and maintain productivity at higher levels is also respected by everyone. We should see that these public sector units in the basic industries justify the confidence that has been vested in them and the amount of capital ploughed into them.

With these words, I hope we would be able to get the support of the House as well as of the leaders of labour unions and the various State Governments and step by step try to go ahead towards self-sufficiency and build the know-how and technical equipment in the steel and allied industries.

MR. DEPUTY-SPEAKER : With the permission of the House, I will now put all the cut motions together to the vote of the House.

All the cut motions were put and negatived.

MR. DEPUTY SPEAKER : The question is :

"That the respective sums not exceeding the amounts shown in the fourth column of the order paper, be granted to the President, to *complete* the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of the heads of demands entered in the second column thereof against Demands Nos. 83, 84 and 130, relating to the Ministry of Steel and Heavy Engineering."

The motion was adopted.

[*The Motions for Demands for Grants which were adopted by the Lok Sabha, are reproduced below—Ed.*]

DEMAND NO. 83—MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING

"That a sum not exceeding Rs. 19,00,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of 'Ministry of Steel and Heavy Engineering.'

DEMAND NO. 84—OTHER REVENUE EXPENDITURE OF THE MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING

"That a sum not exceeding Rs. 1,33,68,000 be granted to the President to complete

the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of 'Other Revenue Expenditure of the Ministry of Steel and Heavy Engineering'."

DEMAND NO. 130—CAPITAL OUTLAY OF THE MINISTRY OF STEEL AND HEAVY ENGINEERING

"That a sum not exceeding Rs. 1,42,53,75,000 be granted to the President to complete the sum necessary to defray the charges which will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 1970, in respect of 'Capital Outlay of the Ministry of Steel and Heavy Engineering'."

15.40 hrs.

STATEMENT *RE*: MESSRS. SYNTHETICS AND CHEMICALS

MR. DEPUTY-SPEAKER : Before we take up for discussion and voting the Demands for Grants relating to the Ministry of Law, a point was raised here regarding Synthetics and Chemicals and the hon. Minister will make a statement on that.

THE MINISTER OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI F. A. AHMED) : Sir, I was informed that some hon. Members had raised the question regarding dispute between the Firestone Company and Kilachand. The only thing I would like to inform the House is that I have received representations from various quarters regarding this matter. Our present information is that a meeting is going to be held today for the purpose of approving the sole selling agency agreement and another meeting has also been called by shareholders tomorrow for disapproving this agreement. The position is that as long as this subject is before the shareholders' meeting it is not possible under the law for us to interfere, but if the agreement is disapproved the matter falls and there is nothing to be done. But if it is approved it has to come to the company Law Board. Under Section 294 of the Companies Act, when the matter comes to us we shall certainly look as to what is in the interest of the shareholders after the whole matter has been examined. What is done in this meeting will be taken into consideration by us. So far as my information goes, the shareholders on both the sides are canvassing their cases. I think the only thing we can do is to leave it to the shareholders to decide whether they will approve of the agreement or not. After that has been approved it will come to us and then on the basis of facts and material available to us the Company Law Board will take necessary action.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : Sir, we wanted Government's intervention only on one ground that LIC has invested money in this. Am I to understand that the entire thing has been left in the hands of the shareholders ? After all, LIC is an autonomous corporation working under a particular Ministry which is answerable to this House. Therefore, will a Company Law Officer, a Secretary or a Joint Secretary, also attend the meeting as an observer to see that the interest of LIC money is safe ? Otherwise, Sir, Shri Kilachand may take a decision or the other man may take another decision. Once they approve or disapprove, the final approval should depend on the approval given by the Company Law Board.

SHRI F. A. AHMED : So far as LIC is concerned the hon. Member must appreciate that LIC is as much a shareholder as any other person or any other body, and that LIC also functions under the control and guidance of the Ministry of Finance. I have no reason to doubt that as a shareholder they will not take necessary action to look after the interest of their own as well as the other shareholders. So far as my information goes they are in possession of all the facts and materials which are necessary to take a decision in this matter.

15.44 hrs.

DEMANDS FOR GRANTS—*Contd.*

MINISTRY OF LAW

MR. DEPUTY-SPEAKER : The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 73 and 74 relating to the Ministry of Law for which one hour has been allotted.

Hon. Members present in the House who are desirous of moving their cut motions may send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of